- पर्यटन को उद्योग बनाना साहसिक दांव...
- नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग
- महिला सशक्तिकरण के दो वर्ष

लाल कालीन, नीला आसमान और एक कड़वा सच

लाईफ वर्सिटी

वर्ष- 03 अंक -09 दिसम्बर 2025 मूल्य - 50 रू.

www.scgnews.in

2 साल साय सरकार

पहचान से आत्मविश्वास तक

Postal Regn. No. C.G./RYP DN/108/2024-26 RNI No. CHHHIN/2023/87466

200 यूनिट तक बिजली पर बिल हाफ

प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ

- घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक विद्युत खपत पर 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ
- 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ

क्षमता	सब्सिडी केन्द्र+ राज्य सरकार
1 किलोवॉट	30+15 = 45 हजार
2 किलोवॉट	60+30 = 90 हजार
3 किलोवॉट	78+30 = 1 लाख 8 हजार

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- **मुफ़्त बिजली:** 3 किलोवाट क्षमता वाला रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर, प्रति माह 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन
- **अतिरिक्त बचत:** 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से ₹26,000 प्रति वर्ष तक बचत
- **सब्सिडी लाभ:** केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापना पर 45,000, 2 किलोवॉट पर 90,000 रुपए और 3 किलोवॉट के सोलर प्लांट की स्थापना पर अधिकतम 1,08000 रुपए की सब्सिडी
- **लोन सुविधा:** सोलर प्लांट की स्थापना पर बैंकों द्वारा 6% ब्याज दर पर ऋण
- **अतिरिक्त आय:** उत्पन्न अधिशेष बिजली को ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय

संवाद- 13558/40

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

सलाहकार मण्डल

डॉ अनिल गुप्ता	रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान	रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल	नई दिल्ली
प्रो तपन मोहन्ति	ओड़िसा

सलाहकार (मीडिया मार्केटिंग एंड एआई)
भूपेन्द्र सिंग

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979

मध्यप्रदेश कार्यालय
अनामिका पाण्डेय
गोकुलधाम बेलौहान टोला,
सामान, रीवा मप्र

प्रतिनिधि

अम्बुज अग्निहोत्री	जबलपुर
संजीव पाण्डेय	भोपाल
राजेश सिंह	बिलासपुर

कानूनी सलाहकार
संजयेंदु पंड्या

परिकल्पना
रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर

03 छत्तीसगढ़, संघर्ष से संकल्प तक पहचान से आत्मविश्वास तक

6 पर्यटन को उद्योग बनाना छत्तीसगढ़ का साहसिक दांव

10 छत्तीसगढ़ में आवासीय बदलाव

14 नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग

18 लाल कालीन, नीला आसमान और एक कड़वा सच

27 मन का युद्ध भूमि

महिला सशक्ति करण के दो वर्ष	8
छत्तीसगढ़ का हरित भविष्य	12
1,742 हेक्टेयर जंगल की आह	17
भारतीय राजनीति के नक्षत्र अटल जी	20
एआई विकास का साथी या..	22

SCAN & PAY

UPI ID: 329944413263914@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सत्ती बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

मजबूत सत्ता, कमजोर संवाद

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

वर्तमान राजनीति की सबसे बड़ी पहचान है–मजबूत सत्ता और कमजोर संवाद। बहुमत के बल पर फैसले लिए जा रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से वैध हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से असहज हैं। संसद बहस का मंच कम और शोर का अखाड़ा अधिक बनती जा रही है। विधेयक पारित हो जाते हैं, पर उन पर विचार नहीं होता; सवाल पूछना अवरोध और असहमति को संदेह की नज़र से देखा जाता है। यह स्थिति केवल विपक्ष की कमजोरी नहीं, बल्कि सत्ता की आत्मसंतुष्टि का संकेत है।

विपक्ष आज दोहरे संकट में है–विश्वसनीय वैकल्पिक एजेंडे का अभाव और सत्ता-विरोध को ही राजनीति मान लेने की भूल। जब विपक्ष समाधान नहीं देता, केवल आरोप लगाता है, तो वह चुनौती नहीं बनता, सिर्फ़ शोर बनकर रह जाता है। ऐसी राजनीति सत्ता को मजबूत करती है, लोकतंत्र को नहीं।

आज राजनीति तर्क से नहीं, भावना से संचालित हो रही है। धर्म, राष्ट्रवाद और पहचान जैसे विषयों को इस कदर भावनात्मक बना दिया गया है कि विवेकपूर्ण चर्चा लगभग असंभव हो गई है। राजनीति यह तय नहीं कर रही कि देश को क्या चाहिए, बल्कि यह तय कर रही है कि जनता को क्या महसूस कराना है।

इस माहौल को सबसे अधिक ऊर्जा मुख्यधारा मीडिया दे रहा है। मीडिया सवाल पूछने के बजाय पक्ष तय करता दिख रहा है। प्राइम टाइम पर मुद्दे नहीं, मूड गढ़े जा रहे हैं। जनता को सूचना नहीं, संस्करण मिल रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यही है–यह राजनीति नागरिक बना रही है या केवल समर्थक और विरोधी? लोकतंत्र सवालों से चलता है। और जब राजनीति सवालों से भागने लगती है, तो समाज जवाब खोजने सड़कों पर उतर आता है।

संघर्ष से संकल्प तक पहचान से आत्मविश्वास तक

36 गढ़

इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता रही है– निर्णय की स्पष्टता और क्रियान्वयन की गति। विकास यहाँ भाषणों में नहीं, प्रक्रियाओं में दिखा। फाइलों की जड़ता टूटी और शासन की उपस्थिति ज़मीन पर महसूस हुई।

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार के दो वर्ष पूरे होना किसी औपचारिक उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि शासन की दिशा को परखने का क्षण है। यह वह समय होता है जब सरकार को उसके दावों से नहीं, उसके असर से आँका जाता है। 'मोदी की हर गारंटी पूरी होगी' यदि सिर्फ़ नारा होता, तो इसकी उम्र चुनाव तक सीमित रहती, लेकिन इन दो वर्षों में यह वाक्य प्रशासनिक व्यवहार में बदला दिखाई देता है।

इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता रही है—निर्णय की स्पष्टता और क्रियान्वयन की गति। विकास यहाँ भाषणों में नहीं, प्रक्रियाओं में दिखा। फाइलों की जड़ता टूटी और शासन की उपस्थिति ज़मीन पर महसूस हुई।

सबसे निर्णायक बदलाव राज्य की सुरक्षा नीति में दिखा। बस्तर अब केवल हिंसा के आँकड़ों से नहीं पहचाना जा रहा। सड़क, मोबाइल नेटवर्क और प्रशासन की निरंतर मौजूदगी ने भरोसे का वातावरण बनाया है। यह नक्सल उन्मूलन को केवल सैन्य अभियान नहीं, सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत बनाता है।

महिला सशक्तिकरण के मामले में सरकार ने महिलाओं को लाभार्थी नहीं, भागीदार के रूप में देखा। सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता को जोड़ने की कोशिश साफ़ नज़र आती है। उद्योग और निवेश नीति ने भी संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ अब केवल संसाधनों का राज्य नहीं, अवसरों का राज्य बनना चाहता है—ताकि युवा रोज़गार के लिए बाहर नहीं, भीतर भविष्य तलाशें।

ऊर्जा सुधार, हरित परियोजनाएँ और पर्यटन विकास—ये सब मिलकर एक शांत लेकिन प्रभावी परिवर्तन की कहानी कहते हैं।

हालाँकि चुनौतियाँ शेष हैं—रोज़गार का विस्तार, उद्योगों की विविधता और बस्तर का पूर्ण पुनर्वास। दो साल में सरकार ने दिशा दी है, अब चुनौती है इस गति को टिकाऊ

बदलाव में बदलने की। लोकतंत्र में सत्ता की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है।

एक राज्य, जो 25 वर्षों में केवल भूगोल नहीं बना, बल्कि भरोसा बन गया

1 नवंबर 2000। भारत के मानचित्र पर एक नया नाम जुड़ा— छत्तीसगढ़। पर उस दिन सिर्फ एक राज्य नहीं बना था, उस दिन वर्षों की उपेक्षा, संसाधनों की लूट और प्रशासनिक दूरी से जूझते एक अंचल ने अपने भविष्य की कमान खुद थामने का साहस किया था। आज, रजत जयंती के इस पड़ाव पर खड़ा छत्तीसगढ़ पीछे मुड़कर देखता है—तो संघर्ष दिखाई देता है, आगे देखता है—तो आत्मविश्वास। यह यात्रा आसान नहीं थी। यह कहानी है बुनियादी सुविधाओं की कमी से लेकर सुशासन की संरचना तक, धान के खेतों से लेकर डिफेंस और एआई जैसे भविष्य के उद्योगों तक, और नक्सल प्रभावित अंधेरे से विकास की रौशनी तक।

राज्य गठन : उम्मीदों का जन्म, चुनौतियों का बोझ

राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ के सामने सवाल थे— सड़कें कहाँ हैं? अस्पताल कितने हैं? स्कूलों में शिक्षक हैं या सिर्फ भवन? और सबसे कठिन—नक्सल प्रभावित इलाकों में शासन की उपस्थिति कैसे हो? कमजोर अधोसंरचना, सीमित औद्योगिक आधार, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक शून्यता— यह विरासत में मिला सच था। लेकिन शुरुआती वर्षों में सरकारों ने यह समझा कि

अगर नींव मजबूत होगी, तो इमारत खुद खड़ी होगी। नवा रायपुर (आज का अटल नगर) की परिकल्पना, जिलों-तहसीलों का पुनर्गठन, पंचायतों और नगरीय निकायों को अधिकार— यहीं से छत्तीसगढ़ ने विकेंद्रीकृत विकास का रास्ता चुना।

जब किसान नीति का केंद्र बना

छत्तीसगढ़ केवल 'धान का कटोरा' नहीं, यह वह राज्य है जहाँ किसान राजनीति का औज़ार नहीं, नीति का आधार बना। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, डिजिटल पंजीकरण, समयबद्ध भुगतान— इन फैसलों ने किसान को यह भरोसा दिया कि उसकी मेहनत बाजार की दया पर नहीं छोड़ी जाएगी। आज 2300 से अधिक उपार्जन केंद्र, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी, और रू.3100 प्रति क्विंटल का मूल्य— यह

सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाली गई सीधी ऑक्सीजन है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के खातों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुँची, जिसका असर ट्रैक्टर बिक्री से लेकर शहरी बाजार तक दिखा।

अधिकार से आत्मसम्मान तक

छत्तीसगढ़ की आत्मा उसके आदिवासी समाज में बसती है। यहाँ विकास का मतलब जंगल से विस्थापन नहीं, बल्कि जंगल के साथ अधिकार है। वन अधिकार पट्टे, छात्रावास-छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य और पोषण योजनाएँ— इन सबका उद्देश्य केवल सहायता नहीं, बल्कि समान अवसर देना रहा। नई छात्रवृत्ति प्रणाली इसका उदाहरण है— जहाँ पहले छात्र जनवरी-मार्च तक इंतज़ार करते थे, अब आवेदन करते ही समयबद्ध भुगतान हो रहा है। रू.255 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का ऑनलाइन अंतरण यह बताता है कि सुशासन अब घोषणा नहीं, प्रक्रिया बन चुका है।

सहायता से स्वाभिमान तक

महतारी वंदन योजना कोई कल्याणकारी योजना भर नहीं है, यह महिलाओं को आर्थिक पहचान देने की पहल है। 70 लाख महिलाओं

के खातों में रू.14,000 करोड़ से अधिक की राशि— इसका असर सिर्फ़ घर की रसोई तक सीमित नहीं रहा, यह बचत, छोटे व्यवसाय और निर्णय क्षमता तक पहुँचा। महिला स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रीढ़ दी है।

कुटीर उद्योग - आत्मनिर्भरता का असली आधार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट विश्वास है— छत्तीसगढ़ की असली ताकत गांवों में है। CMEGP और PMEGP जैसी योजनाओं ने कुटीर और ग्रामोद्योग को केवल जीवित नहीं रखा, बल्कि आर्थिक आंदोलन बना दिया। मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर फ्लाई ऐश ब्रिक्स, डेयरी से लेकर फूड प्रोसेसिंग— यह स्वरोजगार अब मजबूरी नहीं, सम्मानजनक विकल्प बन रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव की सक्रिय भूमिका ने परंपरागत कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ा।

बंदूक से नहीं, भरोसे से जीत

छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती—नक्सलवाद। पर बीते वर्षों में रणनीति बदली। सुरक्षा के साथ विकास, संवाद के साथ योजनाएँ। 'नियद नेल्ला नार' योजना के तहत 69 सुरक्षा कैंप अब सिर्फ़ सुरक्षा केंद्र नहीं, सेवा केंद्र बन चुके हैं। बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम— यह आयोजन बताते हैं कि यह क्षेत्र अब पहचान बदल रहा है।

सुशासन और तकनीक -सत्ता से सेवा तक

ई-गवर्नेंस, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सेवा गारंटी— यह सब प्रशासनिक अनुशासन की ओर संकेत करते हैं। नवा रायपुर में नया विधानसभा भवन केवल एक इमारत नहीं, यह विकसित छत्तीसगढ़ के आत्मविश्वास का प्रतीक है।

जशपुर - विकास का जीवंत उदाहरण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला जशपुर इन दो वर्षों में विकास की प्रयोगशाला बन गया।

- 52,760 पीएम आवास

- महिलाओं को रू.448 करोड़ की सहायता
- किसानों को बोनस और सम्मान निधि
- स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शिक्षा—हर मोर्चे पर निवेश

यह बताता है कि नीतियाँ जब ज़मीन से जुड़ती हैं, तो नतीजे दिखते हैं।

भविष्य की ओर आत्मविश्वास

25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि राज्य सिर्फ़

बजट से नहीं, दृष्टि और निर्णय से बनते हैं। आज छत्तीसगढ़ कृषि में मॉडल है, सुशासन में उदाहरण है, और भविष्य के उद्योगों में संभावना। रजत जयंती पर यह सिर्फ़ जश्न नहीं, यह संकल्प है— कि विकास का यह पहिया अब रुकने वाला नहीं। हाँ 25 साल बाद अब छत्तीसगढ़ यह कह सकता है कि— हाँ, हमने पहचान बनाई हाँ, हमने गलतियाँ की और हाँ, हमने उनसे सीखा भी-

लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्योंकि

- संसाधन अब भी हैं
- चुनौतियाँ अब भी हैं
- लेकिन बहाने अब नहीं होने चाहिए

रजत जयंती , तालियाँ बजाने का नहीं, जवाबदेही तय करने का अवसर है। और अगर राजनीति यह आत्मविश्वास बनाए रख पाई, तो अगली जयंती सिर्फ़ उत्सव नहीं होगी— उदाहरण होगी।

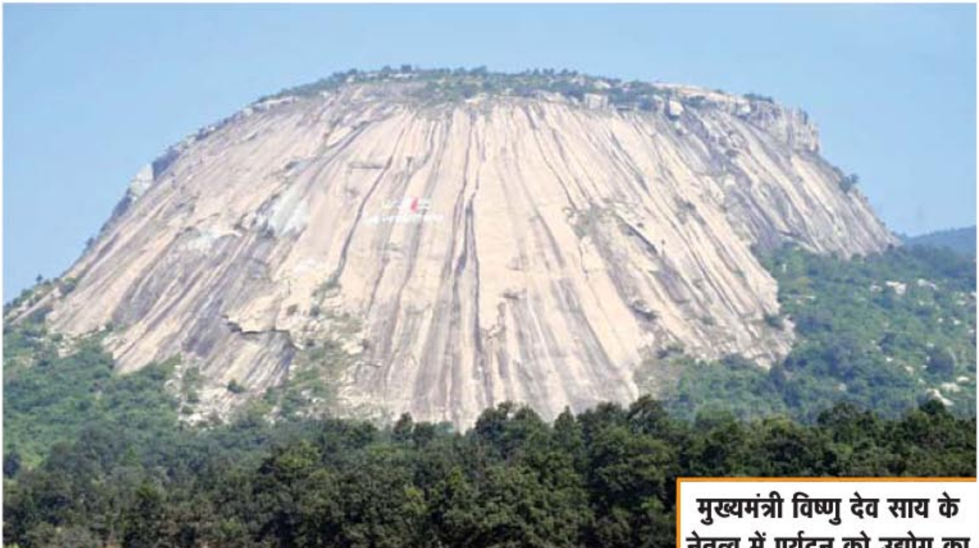

> **मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो यह फैसला सिर्फ़ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी निर्णायक माना जाना चाहिए।**

पर्यटन को उद्योग बनाना छत्तीसगढ़ का साहसिक दांव

छत्तीसगढ़ उन गिने-चुने राज्यों में है जहाँ प्रकृति ने राजनीति से पहले निवेश कर दिया था। विशाल वन,अविरल नदियाँ, प्राकृतिक जलप्रपात, हज़ारों साल पुरानी आस्था और सभ्यता— यह सब यहाँ पहले से मौजूद था। कमी सिर्फ़ एक थी— राज्य की दृष्टि। अब हाल के वर्षों में जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो यह फैसला सिर्फ़ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी निर्णायक माना जाना चाहिए। क्योंकि पर्यटन को उद्योग मानना यह स्वीकार करना है कि—

- **जंगल बोझ नहीं हैं**
- **आदिवासी संस्कृति बाधा नहीं है**
- **और आस्था पिछड़ापन नहीं है**

ईको-टूरिज्म : विकास बनाम विनाश की बहस का व्यावहारिक उत्तर

छत्तीसगढ़ में वर्षों से एक बहस रही— जंगल बचाएँ या रोज़गार दें? ईको-टूरिज्म ने

इस बहस को नारे से निकालकर नीति में बदलने की कोशिश की है। वनांचल में रिसॉर्ट, होटल चेन, और सबसे महत्वपूर्ण— होम-स्टे पॉलिसी। यह सिर्फ़ पर्यटक को ठहराने की व्यवस्था नहीं, यह स्थानीय आदिवासी को पर्यटन का भागीदार बनाने की राजनीति है। अगर यह नीति ईमानदारी से लागू हुई, तो छत्तीसगढ़ 'प्रोजेक्ट बनाम विस्थापन' की पुरानी राजनीति से बाहर आ सकता है।

राम वन गमन पथ - आस्था का सांस्कृतिक पुनर्संयोजन

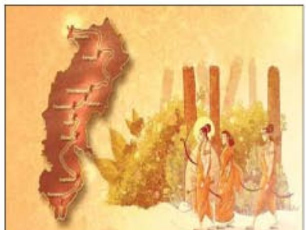

छत्तीसगढ़ को अक्सर धार्मिक पर्यटन के नक्शे में हाशिए पर रखा गया। जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास के दस वर्ष इसी धरती पर बिताए। कोरिया के सीतामढ़ी-हरचौका से सुकमा के रामाराम तक राम वन गमन पथ का विकास केवल धार्मिक परियोजना नहीं है। यह उस ऐतिहासिक उपेक्षा का सांस्कृतिक प्रत्युत्तर है जिसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका रामकथा में दबा दी गई थी। यह आस्था का राजनीतिकरण नहीं, बल्कि इतिहास का पुनर्स्थापन है।

पाँच शक्तिपीठ - आस्था को सर्किट में बदलने की रणनीति

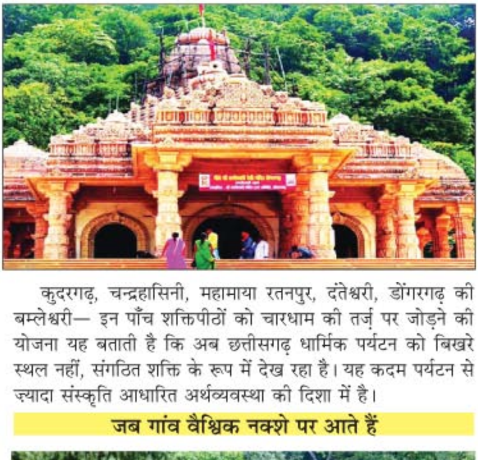

कुदरगढ़, चन्द्रहासिनी, महामाया रतनपुर, दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ की बम्लेश्वरी— इन पाँच शक्तिपीठों को चारधाम की तर्ज़ पर जोड़ने की योजना यह बताती है कि अब छत्तीसगढ़ धार्मिक पर्यटन को बिखरे स्थल नहीं, संगठित शक्ति के रूप में देख रहा है। यह कदम पर्यटन से ज़्यादा संस्कृति आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में है।

जब गांव वैश्विक नक्शे पर आते हैं

धुड़मारास का संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में चुना जाना कोई संयोग नहीं है। यह उस मॉडल की मान्यता है जहाँ पर्यटन स्थानीय जीवन को रौंदता नहीं, सहारा देता है। इसी तरह जशपुर का मधेश्वर पहाड़— दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग— गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना छत्तीसगढ़ को आस्था और एडवेंचर— दोनों मानचित्रों पर स्थापित करता है। ?10 करोड़ की केंद्र सहायता अगर सही दिशा में लगी, तो यह स्थल केदारनाथ या अमरनाथ की तरह सिर्फ़ मंदिर नहीं, अनुभव बन सकता है।

राजिम से चंदखुरी तक - छत्तीसगढ़ की धार्मिक रीढ़

राजिम— जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है, राजीव लोचन मंदिर, कुंभ कल्प— यह सब बताता है कि छत्तीसगढ़ की आस्था नक़्शे में नई नहीं, राजनीति में उपेक्षित रही है। चंदखुरी में माता कौशल्या, शिवरीनारायण में माता शबरी, डोंगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर— यह सब मिलकर छत्तीसगढ़ को रामायण और शक्तिपूजा का केंद्रीय भूगोल बनाते हैं।

सिरपुर से सिंघनपुर-इतिहास जो किताबों से बाहर आना चाहता है

सिरपुर— जहाँ चीनी यात्री आए, जहाँ बौद्ध विहार थे, जहाँ शैव, वैष्णव और बौद्ध परंपरा मिली। भोरमदेव— खजुराहो की छाया नहीं, छत्तीसगढ़ की मौलिक शिल्प चेतना। सिंघनपुर और रामगढ़ की गुफाएँ— जहाँ आदिमानव ने चित्र बनाए, जहाँ भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला के संकेत हैं। ये स्थल सिर्फ़ पर्यटन नहीं, इतिहास की राजनीति हैं— जो अब तक राष्ट्रीय विमर्श से बाहर रही।

चित्रकोट से मैनपाट- प्रकृति का आत्मविश्वास

चित्रकोट— भारत का नियाग्रा। तीरथगढ़— जहाँ पानी गिरता नहीं, नृत्य करता है। मैनपाट— छत्तीसगढ़ का शिमला, मिनी तिब्बत। यह सब राज्य की उस क्षमता का संकेत हैं जहाँ पर्यटन भीड़ नहीं, शांति बेच सकता है।

अंतिम सवाल -क्या छत्तीसगढ़ पर्यटन को सिर्फ़ दिखाएगा या जिएगा?

पर्यटन नीति बनाना आसान है। इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना संभव है। लेकिन असली सवाल यह है—

- क्या स्थानीय व्यक्ति सिर्फ़ कर्मचारी रहेगा या साझेदार बनेगा?
- क्या जंगल सिर्फ़ बैकड्रॉप रहेगा ■ या संरक्षित जीवन बनेगा?

अगर सरकार इस संतुलन को साध पाती है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन का उपभोक्ता नहीं, पर्यटन का मॉडल बन सकता है। और तब यह कहना गलत नहीं होगा— छत्तीसगढ़ अब सिर्फ़ संसाधनों का राज्य नहीं, संभावनाओं की राजनीति बन चुका है।

महिला सशक्तिकरण के दो वर्ष

“

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने बीते दो वर्षों में महिला सशक्तिकरण को केवल एक कल्याणकारी एजेंडा नहीं, बल्कि विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का केंद्रीय स्तंभ बनाया है। यह बदलाव घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और निर्णय क्षमता—इन पाँच आधारों पर महिलाओं के जीवन में ठोस परिवर्तन के रूप में सामने आया है।

”

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का स्पष्ट मानना है कि 'छत्तीसगढ़ की प्रगति तब तक अधूरी है, जब तक राज्य की हर महिला आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित जीवन नहीं जीती।' इसी सोच के अनुरूप शासन की नीतियाँ, बजट और क्रियान्वयन ढांचा महिलाओं को केंद्र में रखकर पुनर्गठित किया गया है।

आर्थिक स्वतंत्रता की रीढ़ महतारी वंदन योजना

महिला सशक्तिकरण की इस यात्रा में महतारी वंदन योजना एक निर्णायक हस्तक्षेप बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को वर्चुअली प्रारंभ की गई इस योजना के तहत लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है। अब तक 22 किश्तों में 14,306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में पहुंच चुकी है।

यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक पहचान और निर्णय क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसके साथ ही महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि राज्य की विकास नीति का केंद्र बिंदु महिला है।

संपत्ति, कौशल और स्वावलंबन की दिशा में कदम

महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट जैसे निर्णयों ने सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। इसी क्रम में 368 महतारी सदनों का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जहां प्रशिक्षण, परामर्श, कौशल विकास और सहायता सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान शुरू कर शासन ने पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूत किया है।

स्व-सहायता समूह और ग्रामीण महिला अर्थव्यवस्था

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में विभाग ने स्व-सहायता समूहों को सशक्त आर्थिक इकाई के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर—इन छह जिलों में रेडी-टू-ईट का कार्य महिला समूहों को सौंपा गया है।

इसके अलावा 42,878 महिला समूहों को 12,946.65 लाख रुपये का रियायती ऋण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है।

दीदी ई-रिक्शा योजना, सिलाई मशीन सहायता, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना और मिनीमाता महतारी जतन योजना ने श्रमिक और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए आजीविका के नए द्वार खोले हैं।

कन्या, किशोरी और उद्यमी- तीनों पर फोकस

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि का बड़ा हिस्सा—35,000 रुपये सीधे कन्या के खाते में—जमा करने का निर्णय सामाजिक सम्मान और वित्तीय सुरक्षा दोनों को मजबूत करता है। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वहीं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी पहलों के लिए 800 करोड़ रुपये निर्धारित कर महिला उद्यमिता को नई ऊँचाई दी गई है।

किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए शुचिता योजना के तहत 2,000 स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें, तीन लाख से अधिक किशोरियों को स्वच्छता सामग्री, और छात्राओं को साइकिल वितरण जैसे कदम सामाजिक बदलाव के संकेत हैं।

सुरक्षा और सम्मान- राज्य का स्पष्ट संदेश

महिला सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश में नई मिसाल कायम की है। नवाबिहान योजना घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मनोसामाजिक सहायता प्रदान कर रही है।

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटर का डिजिटल संस्करण और उसकी मानक प्रक्रिया लागू की।

181 महिला हेल्पलाइन और डायल 112 के एकीकृत संचालन से संकट की स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित हुई है। वहीं सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 2.18 लाख से अधिक विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह सहायता दी जा रही है।

बाजार से वैश्विक मंच तक

नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण महिला समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। जशपुर की आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित 'जशप्योर' ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास महिला उद्यमिता की नई कहानी लिख रहे हैं।

नीतिगत स्पष्टता और भविष्य की दिशा

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महतारी वंदन, नवाबिहान, लखपति दीदी और शुचिता जैसी योजनाएं महिलाओं के समग्र विकास का आधार हैं।

वर्ष 2025-26 में 8,245 करोड़ रुपये का बजट आवंटन यह स्पष्ट करता है कि महिला कल्याण केवल एक विभागीय विषय नहीं, बल्कि राज्य की विकास रणनीति का मूल तत्व है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की सक्रिय भूमिका में छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा, नई उम्मीद और नए विश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा है—जहाँ महिला केंद्र में है, और विकास उसके साथ चलता है।

छत्तीसगढ़ में आवासीय बदलाव राहत और विकास की असली परीक्षा

छत्तीसगढ़ में आवास अब केवल छत का सवाल नहीं रहा। यह आर्थिक राहत, शहरी नियोजन, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन का साझा विमर्श बन चुका है। बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने आवास को कल्याण की परिधि से निकालकर विकास की मुख्यधारा में लाने की ठोस कोशिश की है।

नवा रायपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85वीं बोर्ड बैठक इसी बदलते दृष्टिकोण का संकेत देती है। अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए फैसले सीधे उन हजारों परिवारों से जुड़े हैं, जिनके लिए आवास एक सपना था, लेकिन किश्तों और ब्याज का बोझ बाधा बन रहा था।

किश्तों के बोझ से राहत की नीति

स्ववित्तीय और भाड़ाक्रय श्रेणी के कई हितग्राही लंबे समय से किश्तें समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे। इसका सीधा असर यह हुआ कि मूल राशि से अधिक बोझ विलंब ब्याज के रूप में बढ़ता चला गया। बोर्ड का यह निर्णय कि एकमुश्त बकाया जमा करने पर 50 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी, न केवल आर्थिक राहत है बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता का भी संकेत है। इसी तरह, वॉटर चार्जेस पर लगे भारी सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट का फैसला यह बताता है कि शासन अब दंडात्मक व्यवस्था की बजाय समाधान-आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है। विक्रय विलेख के साथ ही भौतिक कब्जा देने का निर्णय वर्षों से चली आ रही जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। यह छोटा सा प्रशासनिक बदलाव, नागरिक विश्वास के लिहाज से बड़ा कदम है।

छत्तीसगढ़ में आवास अब केवल छत का सवाल नहीं रहा। यह आर्थिक राहत, शहरी नियोजन, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन का साझा विमर्श बन चुका है। बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने आवास को कल्याण की परिधि से निकालकर विकास की मुख्यधारा में लाने की ठोस कोशिश की है।

राज्य स्तरीय आवास मेला- मांग आधारित नीति की शुरुआत

BTI ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला महज एक आयोजन नहीं था, बल्कि मांग आधारित आवास नीति का परीक्षण था। 2060 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ, 1477 मकानों के लिए 3500 से अधिक आवेदन और 303 करोड़ रुपये का संभावित निवेश—यह आंकड़े बताते हैं कि आवास की वास्तविक मांग कहाँ है। सरकार का यह निर्णय कि पर्याप्त आवेदन मिलने पर ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी, भविष्य में अविक्रित स्टॉक की समस्या को कम करेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना- गति और पैमाना

ग्रामीण आवास के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2016 से 2026 के लक्ष्य के विरुद्ध 26.27 लाख में से 24.37 लाख आवास स्वीकृत और 17.14 लाख पूर्ण—ये आंकड़े केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण हैं। खास बात यह है कि बीते दो वर्षों में लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण हुआ। पिछले छह महीनों में प्रतिदिन औसतन 2000 आवास पूर्ण होना यह दर्शाता है कि योजनाएं अब कागज़ से ज़मीन तक पहुंच रही हैं।

आवास से आजीविका तक- डबरी मॉडल

प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा का अभिसरण करते हुए 10,000 आजीविका डबरी निर्माण की पहल आवास को आजीविका से जोड़ती है। जल संरक्षण, सिंचाई, मत्स्य पालन, बत्तख पालन और सिघाड़ा उत्पादन—ये गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देती हैं। यह मॉडल बताता है कि घर केवल रहने की जगह नहीं, आय का आधार भी बन सकता है।

ऋण से मुक्ति, नीति में सुधार

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, दो वर्ष पहले हाउसिंग बोर्ड 735 करोड़ रुपये के ऋण और 3200 से अधिक अविक्रित संपत्तियों से जूझ रहा था। राज्य सरकार द्वारा ऋण चुकाने और OTS-2 योजना के माध्यम से 30 प्रतिशत तक छूट देने का परिणाम यह हुआ कि 9 महीनों में 1251 संपत्तियों का विक्रय और 190 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अब नई नीति के तहत 60 प्रतिशत या तीन माह में 30 प्रतिशत पंजीयन के बाद ही निर्माण शुरू होगा। यह बाजार-अनुकूल और जोखिम-न्यून नीति है।

नवा रायपुर- ऋण मुक्त शहर से टेक हब तक

नवा रायपुर अटल नगर का देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बनना केवल प्रतीकात्मक उपलब्धि नहीं है। 1345 करोड़ रुपये का ऋण चुकता होना और 5030 करोड़ की संपत्तियों का गिरवी-मुक्त होना निवेश के नए द्वार खोलता है। टेक्सटाइल पार्क, सेमीकंडक्टर और आईटी निवेश, टेक-हब, कॉन्फ्रेंस कैपिटल, वेडिंग डेस्टिनेशन, इनलैंड मरीना, साइंस सिटी, मेडिसिटी—ये सभी परियोजनाएं नवा रायपुर को भविष्य के शहर के रूप में स्थापित कर रही हैं।

विकास के साथ पर्यावरण

रियल टाइम उत्सर्जन निगरानी, स्वचालित नोटिस प्रणाली और कॉमन हज़ार्डस वेस्ट सुविधा यह स्पष्ट करती है कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ का आवास मॉडल अब केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। यह राहत, रोजगार, निवेश, पर्यावरण और शहरी-ग्रामीण संतुलन का साझा ढांचा बन रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की यह दिशा छत्तीसगढ़ को एक वित्तीय रूप से सक्षम, निवेश-अनुकूल और नागरिक-केंद्रित राज्य के रूप में आगे बढ़ा रही है। यही वह आधार है, जिस पर विकसित छत्तीसगढ़ का सपना आकार ले रहा है।

छत्तीसगढ़ का हरित भविष्य

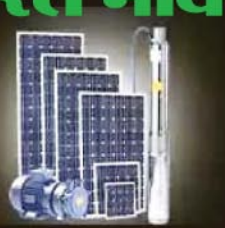

और हमारी जिम्मेदारी

14 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि ऊर्जा केवल सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। प्रदेश में औद्योगिक, कृषि और घरेलू स्तर पर ऊर्जा की खपत हर साल लगभग 15-20 प्रतिशत बढ़ रही है। यदि इस रफ्तार को नियंत्रित नहीं किया गया, तो न केवल बिजली बिल बढ़ेंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी असहनीय हो जाएगा।

क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि सतत विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग अनिवार्य है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्यघर योजना जैसी पहलें स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 1.2 लाख सौर ऊर्जा उपकरण घरों तक पहुँच चुके हैं, जिससे औसतन प्रति परिवार 20-25 प्रतिशत बिजली बचत संभव हुई है।

समान रूप से, औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधार के उपाय अपनाने से प्रति वर्ष करोड़ों रूपये की बचत हो सकती है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। उदाहरण के लिए, बिजली बचत तकनीक अपनाने वाले कुछ औद्योगिक प्लांट्स में पिछले दो वर्षों में 18-20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत हुई है।

भूपेंद्र सवन्नी ने प्रदेशवासियों से स्पष्ट आह्वान किया कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारी योजना या नीति का विषय नहीं है। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयास—जैसे ऊर्जा-सक्षम एलईडी बल्बों का उपयोग, सौर उपकरणों की स्थापना, उपकरणों का समय पर बंद करना—सांस्कृतिक बदलाव ला सकते हैं। यदि हम समय रहते यह कदम नहीं उठाते, तो छत्तीसगढ़ का हरित और स्वच्छ भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

सतत विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग अनिवार्य है। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक घर, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक विद्यालय—सभी को ऊर्जा संरक्षण के प्रति सचेत रहना होगा।

■ भूपेंद्र सवन्नी
क्रेडा अध्यक्ष

'एक सौर पैनल, एक ऊर्जा-सक्षम उपकरण, एक जिम्मेदार नागरिक—यही छोटे कदम मिलकर राज्य को हरित और विकसित बनाएंगे। यदि हम आज जागरूक नहीं हुए, तो भविष्य की पीढ़ियों को भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा,' सवन्नी ने चेतावनी दी।

इस अवसर पर यह भी याद रखना जरूरी है कि ऊर्जा संरक्षण केवल बचत का मामला नहीं है, बल्कि यह रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। ऊर्जा दक्षता से औद्योगिक लागत घटेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा रोजगार पैदा करेगी और पूरे प्रदेश में निवेश-अनुकूल माहौल बनेगा।

छत्तीसगढ़ को हरित और विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य केवल योजनाओं या नीतियों से संभव नहीं है। इसे हर घर, हर उद्योग और हर नागरिक के व्यवहार में उतारना होगा। अगर हम समय रहते ऊर्जा संरक्षण को अपनाएँ, तो हम न केवल बिजली की बचत करेंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करके सतत विकास की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएँगे।

आज का फैसला—कल का भविष्य- ऊर्जा बचाएँ, प्रकृति बचाएँ, छत्तीसगढ़ को हरित और विकसित बनाएँ।

बाल सुरक्षा पर शून्य सहनशीलता

वर्णिका शर्मा

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग

छत्तीसगढ़ में बाल संरक्षण अब केवल कागज़ी नीति या औपचारिक बैठकों का विषय नहीं रह गया है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने सक्रिय हस्तक्षेप, औचक निरीक्षण और क़ानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है, उसने साफ़ संकेत दे दिया है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य में अब शून्य सहनशीलता का दौर शुरू हो चुका है।

इस बदले हुए तेवर की सबसे स्पष्ट झलक हाल ही में कोरबा संप्रेक्षण गृह के औचक निरीक्षण में देखने को मिली। आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के साथ निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आईं, जिनमें बच्चों की देखरेख, सुरक्षा और संस्थागत अनुशासन से जुड़ी चिंताजनक स्थितियां शामिल थीं।उनोने न केवल व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को परखा, बल्कि बच्चों से सीधे संवाद कर उन बातों को सामने लाया, जो अक्सर फ़ाइलों और रिपोर्टों में दबकर रह जाती हैं। बच्चों की जुबानी सामने आई गंभीर शिकायतों और अव्यवस्थाओं के बाद आयोग ने बिना देरी किए प्रकरण दर्ज किया और संबंधित अधिकारियों को सुधार व कार्रवाई के निर्देश दिए।

वर्णिका शर्मा का स्पष्ट कहना है कि 'बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, दुर्व्यवहार या क्रूरता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान महज़ औपचारिक चेतावनी नहीं, बल्कि हालिया कार्रवाइयों के संदर्भ में एक ठोस नीति का संकेत है।

बाल संरक्षण आयोग की सख्ती केवल संप्रेक्षण गृहों तक सीमित नहीं है। हाल के मामलों में स्कूलों से जुड़ी शिकायतों ने भी आयोग का ध्यान खींचा है। नशे की हालत में स्कूल पहुँचने वाले शिक्षकों, बच्चों के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार करने वाले कर्मियों पर आयोग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है।

वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक, पालक या संस्थान से जुड़ा व्यक्ति बच्चों के प्रति क्रूरता या लापरवाही का दोषी पाया गया, तो उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। संदेश साफ़ है—बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाले हर व्यक्ति को स्वयं अनुशासित, संवेदनशील और जिम्मेदार होना होगा।

बीते कुछ महीनों में आयोग द्वारा दर्ज किए गए मामलों, स्कूलों और बाल गृहों में की गई जांचों ने प्रशासनिक तंत्र में हलचल बढ़ा दी है। कहीं बच्चों के साथ मारपीट का मामला, कहीं संप्रेक्षण गृहों से बच्चों का फरार होना, तो कहीं संस्थागत लापरवाही—हर प्रकरण में आयोग की सक्रिय भूमिका यह दर्शाती है कि अब अनदेखी की गुंजाइश बेहद कम बची है। साथ ही, आयोग केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। बाल अधिकार और संरक्षण को लेकर प्रशिक्षण, जागरूकता और संस्थागत सुधार की दिशा में भी पहल की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ही न हों।

छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की मौजूदा कार्यशैली यह संकेत देती है कि राज्य अब बाल संरक्षण को केवल नीति नहीं, बल्कि व्यवहार के स्तर पर लागू करना चाहता है। बच्चों से सीधे संवाद, ज़मीनी निरीक्षण और कानूनी प्रावधानों का सख्त पालन—ये सभी कदम मिलकर एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि बच्चों की दुनिया में लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं है। वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में आयोग का यह रुख न केवल संस्थानों और शिक्षकों के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज के लिए भी एक आईना है—कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग

नबीन के पास लगभग दो दशकों का अनुभव है, जिसमें चुनावी जिम्मेदारियों का सीमित अनुभव शामिल है। वे ऐसे नेता हैं जो जमीन पर उतरकर संगठन का काम समझते हैं। उनके कार्य का दायरा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा; संगठन की नीतियों को लागू करना, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना यह सब उनके नेतृत्व की विशेषता रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और नेतृत्व में एक ऐसा कदम उठाया है, जो केवल पदोन्नति या औपचारिक नामकरण तक सीमित नहीं है। यह कदम संकेत है, रणनीति है और एक राजनीतिक संदेश भी – युवा नेतृत्व को मौका देने और संगठन को नए जोश के साथ चुनावी तैयारियों के लिए तैयार करने का। 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन का नाम आज पार्टी के भीतर एक नए यथार्थ का प्रतीक बन गया है।

पार्टी ने नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीयकार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर न केवल संगठन की मजबूती का संदेश दिया है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी दिया है कि अब भाजपा में युवा नेतृत्व को अवसर देने की नीति सिरे चढ़कर लागू हो रही है। 45 साल की उम्र में पार्टी के अब तक के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नबीन की नियुक्ति, सिर्फ औपचारिक पदोन्नति नहीं है; यह एक रणनीतिक सोच का प्रतीक है जो चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन के आयामों को समेटे हुए है।

नबीन केवल एक युवा नेता नहीं हैं। वे मेहनती, राजनीतिक रूप से जिज्ञासु और पूरी तरह समर्पित संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नबीन सरल और पहुंच योग्य नेता हैं, जो वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल स्थापित करने में माहिर हैं। यही कारण है कि उनकी नियुक्ति सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व रखती है।

लीडरशिप ट्रांजिशन

भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा अब साफ दिखने लगी है। नितिन नबीन को पार्टी का नया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर भाजपा ने संकेत दे दिया है कि अगला बड़ा चेहरा कौन हो सकता है। पार्टी इतिहास में वे इस पद पर पहुंचने वाले केवल दूसरे नेता हैं। उनसे पहले यही जिम्मेदारी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मिली थी।

दिलचस्प यह है कि भाजपा के संविधान में 'वर्किंग प्रेसिडेंट' नाम का कोई पद मौजूद नहीं है। इसके बावजूद 2019 के बाद यह पद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले का सबसे अहम पड़ाव बन गया है। पार्टी के भीतर इसे अब 'ट्रेनिंग ग्राउंड' माना जाता है, जहां अगला अध्यक्ष संगठन की कमान संभालना सीखता है। जून 2019 में जब अमित शाह केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने, तब जगत प्रकाश नड्डा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। छह महीने बाद, जनवरी 2020 में नड्डा औपचारिक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब ठीक वही मॉडल नितिन नबीन पर लागू होता दिख रहा है।

बीजेपी संविधान के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दो कार्यकाल यानी कुल छह साल तक पद पर रह सकता है। नड्डा का कार्यकाल अब अपने अंतिम चरण में है। नितिन नबीन की नियुक्ति की टाइमिंग भी अपने आप में

संदेश देती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, खरमास की अवधि में शुभ राजनीतिक फैसले टाल दिए जाते हैं। यही वजह है कि खरमास से ठीक पहले नबीन को वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित किया गया। सूत्रों के अनुसार, 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

बीजेपी देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में संगठनात्मक चुनाव पूरा कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए यह आवश्यक शर्त होती है। पार्टी नेताओं के अनुसार, अध्यक्ष का चुनाव चार दिनों के भीतर पूरा हो सकता है। हालांकि चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की परंपरा आम सहमति से नाम तय करने की रही है। ऐसे में नबीन का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है।

युवा, पर अनुभवी- दो दशकों का संगठनात्मक सफर

नबीन की राजनीतिक यात्रा बिहार के युवा संगठन से शुरू हुई। एक समय जब भाजपा की जमीनी पकड़ केवल शहरी इलाकों और कुछ सीमित जिलों तक सीमित थी, नबीन ने उस समय से ही संगठनात्मक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उनके पास लगभग दो दशकों का अनुभव है, जिसमें चुनावी जिम्मेदारियों का असीमित अनुभव शामिल है।

वे ऐसे नेता हैं जो जमीन पर उतरकर संगठन का काम समझते हैं। उनके कार्य का दायरा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा; संगठन की नीतियों को लागू करना, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, यह सब उनके नेतृत्व की विशेषता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले छत्तीसगढ़ में उनके कार्यों को पहचाना और बाद में दिल्ली में भाजपा की अभियान टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी को राजधानी में लगभग तीन दशकों के चुनावी सूखे को तोड़ने में मदद मिली।

साधारण शब्दों में कहें, तो नबीन युवा हैं, पर उनका राजनीतिक अनुभव किसी वरिष्ठ नेता से कम नहीं। पाँच बार विधायक और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके नबीन ने

तीन प्रमुख कारण जो नबीन की नियुक्ति के पक्ष में हैं

विश्लेषकों का कहना है कि नबीन के पक्ष में तीन प्रमुख कारण हैं, जो उनकी नियुक्ति को न केवल तर्कसंगत बनाते हैं बल्कि भाजपा के रणनीतिक निर्णय की गहराई को भी उजागर करते हैं।

1. **संगठन और जमीन स्तर की समझ-** नबीन ने हमेशा पार्टी के चुनावी और संगठनात्मक काम को समझने और उसे अंजाम देने पर ध्यान केंद्रित किया। बिहार से लेकर पूर्वी भारत तक उन्होंने पार्टी की जमीन पकड़ को मजबूत किया।
2. **नेतृत्व के साथ तालमेल-** नबीन वरिष्ठ नेतृत्व की शैली और उनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। वे सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम करने में विश्वास रखते हैं।
3. **कठिन कार्यों को पूरा करने की क्षमता-** नबीन ने कई जटिल चुनावी अभियान और संगठनात्मक चुनौतियों को सफलता पूर्वक पूरा किया है। चाहे वह छत्तीसगढ़ अभियान हो या दिल्ली की राजधानी में भाजपा की जीत का रोडमैप, नबीन ने हर बार अपनी रणनीतिक समझ और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया।

नई पीढ़ी का प्रतीक

नबीन की नियुक्ति केवल संगठनात्मक मजबूती का संदेश नहीं देती; यह भाजपा की नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की नीति का प्रतीक भी है। भाजपा लंबे समय से अपने नेतृत्व में युवा और अनुभवी संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में गुजरात में हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। कांग्रेस के 84 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के विपरीत, भाजपा यह संदेश दे रही है कि पार्टी में युवा और मेहनती नेताओं को अवसर मिलेगा। नबीन की नियुक्ति इस दृष्टि से केवल पदोन्नति नहीं, बल्कि एक सशक्त रणनीतिक निर्णय है।

साबित किया है कि वे कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी सफलता हासिल कर सकते हैं।

सामुदायिक और क्षेत्रीय संतुलन

नबीन का सामाजिक और सामुदायिक आधार भी उनके पक्ष में जाता है। वे कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो अक्सर राजनीतिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है और अन्य समुदायों के साथ सीधे संघर्ष में नहीं देखा जाता। यह राजनीतिक संतुलन भाजपा के लिए लाभकारी है। बिहार में उनके संगठनात्मक कार्य और 'जीविका दीदी नेटवर्क' का सफल संचालन पार्टी के लिए मिसाल बन चुका है।

छत्तीसगढ़ अभियान में भी नबीन सक्रिय रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मिलकर चुनावी जिम्मेदारी संभाली और चुनाव से डेढ़ साल पहले से ही राज्य में सक्रिय होकर पार्टी का मजबूत अभियान खड़ा किया। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि यह संकेत भी था कि नबीन नेतृत्व में केवल पद नहीं, बल्कि परिणाम और सक्रियता भी महत्वपूर्ण है।

नेतृत्व की शैली और संगठनात्मक दृष्टिकोण

नबीन नेतृत्व के तरीके को समझते हैं और सीमा पार नहीं करते। वे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का सम्मान करते हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यात्रा और कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंकेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नबीन का यह तरीका भाजपा के लिए लाभकारी होगा। वे केवल चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत बनाएंगे। उनकी शैली में संयम, सक्रियता और रणनीति का अद्भुत मिश्रण है।

भविष्य की संभावनाएँ

नबीन की नियुक्ति कई मायनों में भाजपा की राजनीतिक रणनीति को आकार देगी। पूर्वी भारत में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के साथ ही संगठन में नई ऊर्जा आएगी। यह कदम केवल पदोन्नति का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भाजपा में युवा नेतृत्व को स्थान मिलेगा, अनुभव का सम्मान रहेगा और रणनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियुक्ति से पार्टी को चुनावी और संगठनात्मक लाभ होगा। नबीन की सक्रियता, रणनीतिक सोच और अनुभव का लाभ पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

नितिन नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन, रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत है। यह नियुक्ति पार्टी के लिए नया संदेश है- युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, संगठनात्मक क्षमता का सम्मान होगा और रणनीतिक सोच को महत्व दिया जाएगा।

नितिन नबीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन, रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत है। यह नियुक्ति पार्टी के लिए नया संदेश है– युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, संगठनात्मक क्षमता का सम्मान होगा और रणनीतिक सोच को महत्व दिया जाएगा। 45 साल की उम्र में पांच बार विधायक और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके नबीन ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल पद के लिए नेता नहीं, बल्कि परिणाम, अनुभव और सक्रियता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भाजपा के लिए नबीन की यह नियुक्ति एक नया यथार्थ है – युवा, अनुभवी और रणनीतिक नेतृत्व का संगम।

भविष्य में यह कदम भाजपा के संगठनात्मक और चुनावी समीकरणों को नया आकार देगा। नबीन की सक्रियता और रणनीतिक सोच के साथ, पार्टी केवल पदोन्नति का संदेश नहीं दे रही, बल्कि यह स्पष्ट कर रही है कि भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी और संगठनात्मक अनुभव का संगम ही आने वाले समय की सच्ची शक्ति है।

केते एक्सटेंशन: 1,742 हेक्टेयर जंगल की आह, विकास की आड़ में

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य — मध्य भारत के फेफड़े — ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है- विकास हो या विनाश? जनता के अधिकार हों या कॉर्पोरेट हित की प्राथमिकता? लोकतंत्र का सम्मान हो या बड़े पूंजीपतियों की दादागिरी का भय? 2025 के 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ वन विभाग ने 1,742.60 हेक्टेयर वन भूमि को कोयला खनन (Kente Extension Coal Block) के लिए डायवर्ट करने की सिफ़ारिश केंद्र को भेज दी — एक ऐसा फैसला जो राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक संतुलन को चुनौती देता है। लेकिन संख्या से बड़ी कहानी वही है जो इन हेक्टेयरों के बीच दब गई है — पेड़ों की आहें, आदिवासी समुदायों की आवाज़, और लोकतंत्र का संतुलन।

1,742 हेक्टेयर — एक आंकड़ा नहीं, एक लड़ाई

1,742.60 हेक्टेयर — जब आप इसे ज़मीन में बदलकर देखें, तो यह सिर्फ एक आकड़ा नहीं है। यह लगभग 4.5 लाख पेड़ों का संभावित विलोपन है — नेचर की रेस्पाइरेटरी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। वन विभाग का मानना है कि यह डायवर्ज़न खनन परियोजना के औपचारिक मंज़ूरी चरण के लिए आवश्यक है। लेकिन स्थानीय समुदायों, पर्यावरण संगठनों और विपक्षी नेताओं के लिए यह एक सूचनात्मक, न्यायिक और लोकतांत्रिक आपदा है।

राजनीतिक विश्लेषण यह साफ करने की कोशिश करता है कि यह निर्णय राजनीति के एजेंडे से क्या कह रहा है। बघेल और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक अस्थिरता और कॉर्पोरेट प्राधिकार का परिणाम है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस खनन परियोजना को रोक दिया था। लेकिन वर्तमान भाजपा चलित राज्य सरकार ने वही प्रतिबंध हटा दिया। यह एक ऐसी सरकार है जो चुनावी नारों के तहत 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसी बातें करती है, आज वही जंगलों के कटान को अनुमति दे रही है। यह वही राजनीति है — जहाँ एक फैसले से पैदा हुआ लोक समर्थन दूसरे फैसले से सोशल विद्रोह बन जाता है।

कोयला, कॉर्पोरेट और जनता – कौन किसके लिए?

इस ब्लॉक को राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया है। लेकिन अगले कदम में एडानी एमडीओ (Mine Developer cum Operator) बनता दिखता है — जिसकी हिस्सेदारी से ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। जब सवाल उठता है- 'क्या यह परियोजना जनहित में है?'

तो कुछ नेताओं का कहना है कि यह लोक हिती नहीं — यह कॉर्पोरेट और बिजली नेटवर्क के विस्तार का एक बहाना है। क्या विकास सिर्फ सरकार और कॉर्पोरेट का अधिकार है, या जनता की भी?

कानून बनाम जमीन – जंगल के हक़ के नाम पर

भारतीय कानून, विशेष रूप से Forest Rights Act, 2006 और PESA Act (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act), आदिवासी समुदायों को उनके जंगल भूमि पर अधिकार और निर्णय क्षमता देता है। लेकिन जिस तरह से वैकल्पिक कानूनी तर्क सामने आया है कि ग्रामसभा की स्वीकृतियाँ 'लागू नहीं हुईं', और उजाड़ का रास्ता खुले कानूनी ढांचे से पहले से नियोजित है — ये कानूनी प्रक्रिया का अपमान जैसा प्रतीत होता है। यह एक ही समय में दो सवाल खड़े करता है-

1. क्या फैसलों को लोगों की आवाज़ से ऊपर रखा जा रहा है?
2. क्या कानून अब डिक्शन और औपचारिकताओं का खेल बन गया है?

ये सवाल सिर्फ जंगलों के लिए नहीं — लोकतंत्र के मूल आधार के लिए भी हैं।

आदिवासी आवाज़ — 'हम जल, जंगल, जमीं नहीं देंगे'

जब तक आप जमीन पर खड़े होकर आदिवासी समुदायों से बात नहीं करते — तब तक आप यह नहीं समझ पाते कि जंगल उनके लिए क्या है। यहाँ के गाँवों के लोग कहते हैं —

'हम अपनी जल, जंगल, जमीं को केवल कागज़ पर नहीं देखते; यह हमारी पहचान है।' यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, यह एक संस्कृति का सवाल है।

वे कहते हैं कि पहले भी इन्हें अपने अधिकारों के लिए लंबी यात्राएँ और विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है — कभी 300 किलोमीटर पैदल marcha तक। ये आवाज़ें सांख्यिकीय जानकारियों से ज़्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये जीवन के मामलों से जुड़ी हैं। लोकतंत्र, जंगल और विकास

आज सवाल सिर्फ यह नहीं कि '1,742 हेक्टेयर जंगल डायवर्ट हो रहा है या नहीं।' सवाल यह है-क्या लोकतंत्र, जन अधिकार, धरती की आत्मा और भविष्य हमारी प्राथमिकता हैं? विकास के नाम पर अगर हम जंगलों को काटेंगे, लोकतांत्रिक आदर्शों को कुचलेंगे, आदिवासी समुदायों की आवाज़ को अनसुना करेंगे, और केवल बड़े हितों को प्राथमिकता देंगे — तो हम विकास के मूल प्रश्न से भटक जाएंगे।

यह सिर्फ एक कोल ब्लॉक की लड़ाई नहीं है। यह भारत के भविष्य, उसकी आत्मा, उसकी सामाजिक ताकत और उसकी पारिस्थितिक बुद्धि की लड़ाई है। और इस लड़ाई में कोई छोटा या बड़ा टुकड़ा नहीं है — यह धरती, जनता और नीति के बीच का टकराव है। अगर लोकतंत्र का वचन सचमुच जनता के नाम है, तो आज हसदेव अरण्य की यह गाथा — वन बचाओ की आवाज़ — हमें विकास के वास्तविक अर्थ की याद दिलाती है।

लाल कालीन, नीला आसमान और एक कड़वा सच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुस्कुराहट, गले मिलना और एक ही कार में बैठकर रवाना होनाज यह सब प्रोटोकॉल नहीं था, यह पॉलिटिक्स थी। हाई-वोल्टेज जियोपॉलिटिक्स। यह दृश्य वॉशिंगटन और बीजिंग—दोनों के लिए एक साथ अलर्ट था। संदेश साफ था—भारत-रूस की दोस्ती सिर्फ़ रणनीतिक नहीं, भावनात्मक भी है।

जब दुनिया भर के कैमरे दिल्ली एयरपोर्ट पर टिके थे, तब लाल कालीन पर सिर्फ़ दो नेता नहीं चल रहे थे—एक संदेश चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुस्कुराहट, गले मिलना और एक ही कार में बैठकर रवाना होना, यह सब प्रोटोकॉल नहीं था, यह पॉलिटिक्स थी। हाई-वोल्टेज जियोपॉलिटिक्स। यह दृश्य वॉशिंगटन और बीजिंग—दोनों के लिए एक साथ अलर्ट था। संदेश साफ था—भारत-रूस की दोस्ती सिर्फ़ रणनीतिक नहीं, भावनात्मक भी है।

रूस, भारत और अमेरिका की असहज त्रिकोणीय राजनीति

अमेरिका, यूरोप और चीन—तीनों इस दौरे को संदेह की निगाह से देख रहे थे। वजह स्पष्ट है। भारत-रूस की नजदीकी हमेशा से अमेरिकी रणनीतिक गणना को चुनौती देती रही है। डोनाल्ड ट्रंप—जो सार्वजनिक मंचों पर मोदी की तारीफ़ करते नहीं थकते—उसी ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर भारी-भरकम टैरिफ ठोक दिए। तर्क दिया गया— 'भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी युद्ध क्षमता बढ़ा रहा है।' लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आया। दिल्ली पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद 'इंडिया टुडे' को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने अमेरिका को आईना दिखा दिया—

'अगर अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए रूस से ईंधन खरीद सकता है, तो भारत क्यों नहीं?' यह बयान सिर्फ़ जवाब नहीं था, यह वैश्विक नैरेटिव पर हमला था।कड़वी सच्चाई यह है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ आज भी रूस से तेल, गैस, LNG और यूरेनियम खरीद रहे हैं—खरबों डॉलर का कारोबार। तो फिर निशाने पर सिर्फ़ भारत क्यों?

भरोसे का व्यापारः आंकड़ों के पार की कहानी

पुतिन ने यह भी स्वीकार किया कि 2025 के पहले नौ महीनों में व्यापार थोड़ा घटा है, क्योंकि भारत ने कच्चे तेल का आयात कुछ कम किया। लेकिन बड़ी तस्वीर देखिए—

- 2021- भारत-रूस व्यापार — 13 अरब डॉलर

- 2024-25- बढ़कर — 69 अरब डॉलर
- लक्ष्य (2030)-100 अरब डॉलर

यह रिश्ता तेल का नहीं, भरोसे का है। इसी भरोसे के चलते रूस अब भारत से ज्यादा सामान खरीदने को तैयार है। क्रेमलिन के उप चीफ ऑफ स्टाफ मैक्सिम ओरेखिन का बयान सीधा था—'हम भारत से ज्यादा आयात करना चाहते हैं ताकि व्यापार संतुलित हो।' भारत अब सिर्फ ऊर्जा ग्राहक नहीं, बल्कि रूस के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर बनने की तैयारी में है—

ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स तक। और यह सब तब हो रहा है, जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। यानी भारत साफ कह रहा है—

विदेश नीति वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं, नई दिल्ली की ज़रूरतों पर चलेगी।

मोदी-पुतिन की गर्मजोशी और नीले आसमान पर काला धब्बा

प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट इस पूरी कूटनीति का सार था—'मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करके खुशी हुई। भारत-रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है।' यह दोस्ती नहीं, भारत की स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान है। वह पहचान जो कहती है— भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, अपनी शर्तों पर उभरती सुपरपावर है। लेकिन इसी ऐतिहासिक क्षण के बीच— भारत को भीतर से एक झटका लगा। उसी दिन, उसी समय— जब पुतिन भारत में थे, इंडिगो की हड़ताल ने देश को दो कड़वे सबक दे दिए।

पहला सबक- टाइमिंग भी राजनीति होती है।

यह सिर्फ़ हड़ताल नहीं थी। यह संदेश था। और दुर्भाग्य से यह संदेश विदेशी ताकतों को नहीं, भारत की सरकार को दिया गया। रूसी राष्ट्रपति की यात्रा कोई सामान्य घटना नहीं थी।

यह वह पल था जब—

- अमेरिका नोटिस ले रहा था
- चीन चौकन्ना था
- यूरोप भारत की दिशा पढ़ रहा था

ऐसे समय में हजारों उड़ानों का प्रभावित होना, लाखों यात्रियों का फंसना और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता पर सवाल उठाने का मौका मिलना— इसे मासूम संयोग नहीं कहा जा सकता। हड़ताल का अधिकार है। मांगें जायज़ हो सकती हैं। लेकिन समय का चयन एक टेस्ट था—और इंडिगो उस टेस्ट में फेल हुई।

दूसरा सबक-भारत के पास इंडिगो का विकल्प नहीं है।

यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। जेट

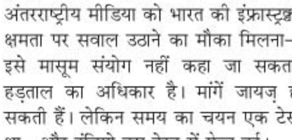

एयरवेज गई, किंगफिशर गई, गो फर्स्ट गई, एयर इंडिया अभी भी खुद को संभाल रही है, विस्तारा सीमित है, बाकी एयरलाइंस नाम भर की हैं। और इस खालीपन में— इंडिगो धीरे-धीरे एकाधिकार बन गई। आज स्थिति यह है कि— अगर इंडिगो एक दिन भी रुक जाए, तो भारत का आधा आसमान ठहर जाता है। यह किसी कंपनी की ताकत नहीं, सिस्टम की कमजोरी है।

सवाल सरकार से नहीं, व्यवस्था से हैं

अब सवाल यह नहीं कि इंडिगो सही थी या गलत। सवाल बड़े हैं—

1. क्या भारत एक निजी कंपनी पर इतना निर्भर हो सकता है?
2. क्या ऐसे संवेदनशील कूटनीतिक दिनों में जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?
3. क्या हमारी skies का future monopolized हो चुका है?

इंडिगो की हड़ताल ने सरकार को नहीं, भारत को झकझोरा है। क्योंकि कोई भी देश तभी महान बनता है जब उसकी कूटनीति, अर्थव्यवस्था और उद्योग—एक-दूसरे के पूरक हों, प्रतिद्वंद्वी नहीं।

अंत में सच्चाई यही है–

इंडिगो ने हड़ताल नहीं की, उसने एक सच उजागर किया। एक कड़वा, बेपरदा और ज़रूरी सच। और अगर पुतिन की मौजूदगी का सम्मान भी एक निजी कंपनी नहीं रख पाती, तो समझ लीजिए– समस्या कर्मचारियों की नहीं, पूरे सिस्टम की है। भारत आज वैश्विक राजनीति में गेम-चेंजर बन रहा है। अब वक्त है कि उसका आसमान भी उतना ही मजबूत बने।

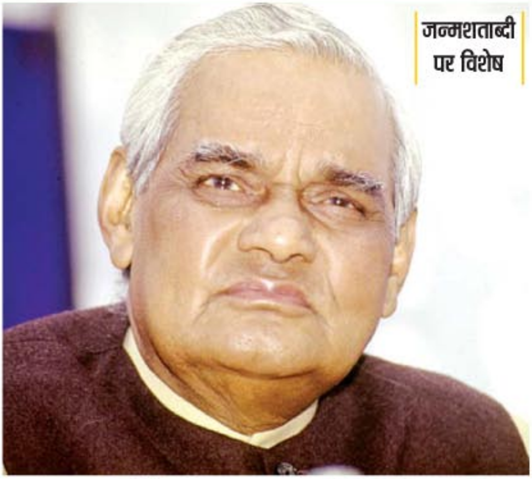

जन्मशताब्दी पर विशेष

भारतीय राजनीति के नक्षत्र अटल जी

चन्द्रशेखर साहू
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

अटल जी जन-जन से प्रेम करने वाले जननायक हैं। वे एक अप्रतिम वक्त ा, संवेदनशील कवि और विचारवान लेखक के साथ भारत के महान नेता है। उनका समग्र व्यक्ति त्व अभ्यर्थना और अवमानना के मोह पाश से मुक्त है।

'हम टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते' अटल बिहारी वाजपेयी जी पर यह उक्ति सटीक बैठती है जब आपातकाल (इमरजेन्सी) के दौरान उन्होंने अपने गम्भीर पीट दर्द के चलते चिकित्सीकीय लाभ और जेल से रिहा होने के लिए इंदिरा जी के संदेश को स्वीकार नहीं किया था। आपातकाल के अनेक प्रसंग त्रासदायी है उसमें भी अटल जी ने अपनी रचनाधर्मी सोच को लोकत्रांत्रिक कलेवर देकर सबको झझकोरा और आशावादी अंतर्धारा को प्रवाहित कर इस उक्ति को राष्टीय धरातल पर चरितार्थ किया। तभी परिवर्तन दुनिया के सामने एक नई राजनीतिक संस्कृतिक का उदय जनता पार्टी के रूप में सन् 1977 में हुआ।

मुख्य तौर पर अटल जी के दीर्घ संसदीय जीवन आज भी लोकतंत्र की आईना के रूप में है, जिसे वर्तमान से लेकर अतीत के राजनीतिक प्रतिबिम्बों को निहारने के साथ ही परखा जा सकता है। अनेक विषयों पर उनका भाषण कालजयी तो है ही सामाजिक जीवन में उम्मीदों का अध्याय भी है। बारहवीं लोकसभा में एक सदस्य के तौर पर यद्यपि मुझे 13 महीने ही कार्य करने का अवसर मिला, परंतु इतने ही कालखण्ड में उनकी संसदीय विधाओं के प्रयोग को मैंने नये आकार लेते हुए देखा। संसद में बहस के दौरान मनुष्य की अदम्य लालसा तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षा पर उनके व्यंग्य वाक्य आज भी राजनीतिक कोहरे में इन्द्रधनुष के लकीर की तरह है, जहाँ भारतीयता की पहचान अपनी चमक अलग दिखाई देती है। तीन

आज से दशक पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक साक्षात्कार में स्वराज और धर्मनिरपेक्षता पर बेवाक विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वदेशी और विदेशी में फर्क काफी संकरा हो गया है। इण्डिया और भारत में अन्तर को भी पाटना इसी पृष्ठभूमि में आज की जरूरत है। भारतीय बने रहने के प्रति अधिक सचेत हो सकते हैं। उनके धुर विरोधी भी स्वीकारते हैं कि अटल जी इस कालखण्ड के सबसे समावेशी राष्ट्रवादी नेता है, जिन्होंने भारतीय अस्मिता को जाग्रत करने के लिए वैश्विक मंच का उपयोग किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण देने का प्रथम राजनेता होने का गौरव हासिल किया।

आर्थिक सुधारों के लिए भी अटल जी ने जो राजनैतिक दर्शन और अपना आधार बनाया वह था 'सर्वानुमिति का मंत्र' जैसे आज भारत के शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व ने भी 'सबका विकास, सबका साथ' को मूलमंत्र की मान्यता दी है।

तेजी से बदलते आर्थिक-सामाजिक ताना-बाना को उन्होंने केवल आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं माना बल्कि उसके लिए सांस्कृतिक मुड़भेड़ (कल्चरल इनकाउण्टर) को कारण बताया है और नब्बे की दशक से शुरू हुये आर्थिक सुधारों में अवरोधों को दूर करने में नया नजरिया को स्वीकार्य बनाया। इसी दो दशक में आर्थिक मंदी का असर वैश्विक पटल पर दृष्टिगोचर हो रहा था तब भी भारत के आम आदमी तथा भारत भूमि के असली ताकत का अहसास उन्होंने विश्व के महाशक्तियों को समय रहते कराया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पोखरण का परमाणु विस्फोट भारत के इस कदम से अमेरिका सहित कई विकसित राष्ट्र अचंभित एवं किंककर्तव्यविमूढ़ थे। आज भी अमेरिका के नीति-नियंता वर्ग को इस बात का मलाल है कि उनके पास इसकी जानकारी पहले कैसे नहीं आ पाई। परमाणु विष्फोट के बाद की परिस्थितियों में सबने देखा कि भारत के परमाणु शक्ति सम्पन्न होते ही अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। तत्काल अटल जी ने संसद में और देशवासियों का अपने सम्बोधन में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के असली ताकत यहाँ के किसान, मजदूर, युवा, महिला हैं। इसलिए आर्थिक प्रतिबंध (इकॉनामिक संक्शन) का असर भारत के अर्थव्यस्था में नहीं पड़ने वाला है, और न ही हम किसी के आगे झुकने वाले हैं। उनकी पक्ति अब फिर से प्रासंगिक हो गई है कि दाँव पर सब कुछ लगा है रूक नहीं सकते

अटल जी जन-जन से प्रेम करने वाले जननायक हैं। वे एक अप्रतिम वक्ता, संवेदनशील कवि और विचारवान लेखक के साथ भारत के महान नेता है। उनका समग्र व्यक्तित्व अभ्यर्थना और अवमानना के मोह पाश से मुक्त है। वे काव्य व्यक्तित्व के छंद बन गये हैं जिसमें उत्साह का प्रवाह निरंतर होता रहता है। हम यह कह सकते हैं कि अपनी स्वच्छ एवं निष्ठा प्रधान विचारधारा के कारण वे उपमेय से उपमान बन गये हैं। आकाश के सप्तर्षि मण्डल को हम आप देखते ही होंगे वह एक नक्षत्र की परिकमा किया करता है। अटल जी मेरी दृष्टि में भारतीय राजनैतिक गगन के नक्षत्र बन गये हैं 'गुंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन-जन कल्याणी। अपढ़ अजान विश्व ने पाई, शीश झुकाकर एक धरोहर ।।'

वज़न घटाने की दवा या मानसिक शॉर्टकट ओजेम्पिक

डॉ अनिल गुप्ता
फाउंडर पॉजिटिव हेल्थ जोन
डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, रायपुर

भारत आज सिर्फ़ शरीर से बीमार नहीं है। भारत बीमार है—जल्द नतीजा चाहने की मानसिकता से। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं—सफलता, शांति, सुंदरता और अब स्वास्थ्य भी। इसी अधीरता, इसी 'फास्ट फ़ॉरवर्ड' सोच के दरवाज़े से भारत में दाखलि हुई है—ओजेम्पिक। एक इंजेक्शन। एक दावा। और अनगिनत सवाल।

भारत में मधुमेह और मोटापा अब व्यक्तिगत समस्या नहीं रहे। यह एक सामूहिक स्वास्थ्य संकट है—लगभग महामारी जैसा। बदलता खानपान, अनियमित नींद, बढ़ता तनाव और निष्क्रिय जीवनशैली ने शरीर को ही नहीं, सोच को भी बीमार कर दिया है। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित दवा ओजेम्पिक का भारत में लॉन्च होना महज़ एक मेडिकल खबर नहीं है। यह एक सामाजिक, मानसिक और वैचारिक घटना है।

दवा क्या है, और उसे क्या बना दिया गया

ओजेम्पिक को मूल रूप से टाइप-2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए विकसित किया गया था। इसका सक्रिय तत्व सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) शरीर में GLP-1 हार्मोन की नकल करता है। इसके प्रभाव स्पष्ट हैं—

भूख कम लगती है, पेट देर से खाली होता है, ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है।

लेकिन पश्चिमी देशों में इसके वज़न घटाने वाले प्रभाव ने इसे धीरे-धीरे एक दवा से ज़्यादा, चमत्कारी इंजेक्शन में बदल दिया। आज इसे देखा जा रहा है— कमर घटाने वाले हथियार की तरह, भूख मारने वाले उपाय की तरह, और सबसे खतरनाक—अनुशासन से बच निकलने के रास्ते की तरह। यह इंजेक्शन शरीर को संकेत देता है—'तुम भरे हुए हो।' लेकिन यह कभी नहीं पूछता— 'तुम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों खाते हो?'

भारत की थाली बनाम पश्चिम की सुई

पश्चिम में मोटापा अक्सर अति का परिणाम है। भारत में मोटापा ज़्यादातर असंतुलन का नतीजा है। यहाँ खाना केवल पेट नहीं भरता—

यह तनाव दबाता है, यह भावनात्मक खालीपन ढकता है और कई बार आत्म-सम्मान की कमी को मीठा बनाकर परोस देता है।

भारत में भोजन मनोविज्ञान से जुड़ा है। ओजेम्पिक इस पूरी प्रक्रिया को एक इंजेक्शन से बायपास कर देता है। लेकिन सवाल बना रहता है— क्या दबाई गई भूख, दबाई गई पीड़ा को भी ठीक कर देती है?

उम्मीद और भ्रम के बीच भारत

भारत जैसे देश में मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है। डायबिटीज़ 'साइलेंट किलर' बन चुकी है और फिटनेस अक्सर केवल 'दिखावे' तक सीमित है। ऐसे में ओजेम्पिक का आगमन दो तरह की प्रतिक्रियाएँ पैदा करता है। एक ओर यह उन मरीजों के लिए उम्मीद है, जिनका वज़न और शुगर डाइट, वॉक और सामान्य दवाओं से नियंत्रित नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरी ओर यह सवाल भी उतना ही ज़रूरी है— क्या हम जीवनशैली सुधारने की बजाय इंजेक्शन पर निर्भर होते जा रहे हैं?

सेलिब्रिटी कल्चर और स्लिमनेस

पश्चिम में कई हॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ द्वारा ओजेम्पिक के इस्तेमाल की खबरों ने इसे 'वज़न घटाने का शॉर्टकट' बना दिया। जिस समाज में— फिट दिखना ज़रूरी है, स्वस्थ होना वैकल्पिक है वहाँ ओजेम्पिक जैसी दवाएँ जल्दी ही मेडिकल टूल नहीं रहतीं, लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन जाती हैं इंस्टाग्राम रील्स में घटता वज़न दिखेगा, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा—इंजेक्शन बंद हुआ तो क्या होगा? मेटाबॉलिज़्म किस कीमत पर बदला? और मन फिर उसी खाने की ओर क्यों लौटेगा?

साइड इफेक्ट- शरीर से आगे की कहानी

डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं— मतली, उल्टी, कमजोरी, हार्मोनल असंतुलन। लेकिन सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट मेडिकल नहीं, मानसिक है। व्यक्ति धीरे-धीरे यह मानने लगता है कि—वह खुद को सुधारने में अक्षम है। और यही सबसे गहरी बीमारी है। आयुर्वेद सदियों से कहता आया है—स्थूलता पेट में नहीं, मन में जन्म लेती है। वात-पित्त-कफ का असंतुलन केवल दवा से नहीं, दृष्टि बदलने से ठीक होता है। ओजेम्पिक शरीर की केमिस्ट्री बदल सकता है, लेकिन—

- नींद का अपराधबोध
- तनाव की आदत
- और स्वाद में छिपी बेचैनी

इनका इलाज नहीं करता।

तो क्या ओजेम्पिक गलत है?

नहीं। ओजेम्पिक एक दवा है—और ज़रूरत पड़ने पर वरदान भी। लेकिन समस्या दवा नहीं है। समस्या यह उम्मीद है कि— एक इंजेक्शन वह काम कर देगा जो जीवनशैली, अनुशासन और आत्म-संवाद को करना चाहिए था।

सवाल इंजेक्शन का नहीं, आत्मनिर्भरता का है भारत को ओजेम्पिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस सोच से ज़रूर डरना चाहिए जो हर बीमारी का समाधान

फार्मेसी की शेल्फ़ में ढूँढती है। क्योंकि सच यह है— स्वास्थ्य तब नहीं आता जब भूख दबाई जाए, स्वास्थ्य तब आता है जब समझ बढ़ाई जाए।

AI विकास का साथी या सुरक्षा की चुनौती?

Bhupender Singh,
Director -
AI, Webority
Technologies

आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल विज्ञान कथाओं का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह हमारे हर दिन का हिस्सा बन चुका है। जब आप अपने फोन में बोलकर कुछ खोजते हैं, गूगल मैप्स पर रास्ता देखते हैं, या सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं-तो पर्दे के पीछे AI ही काम कर रहा होता है।

एक AI विशेषज्ञ के रूप में, मैं अक्सर लोगों को इस तकनीक से डरते हुए देखता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि AI बिजली (electricity) की तरह है। यदि हम इसे सावधानी से इस्तेमाल करें, तो यह हमारे घरों को रोशन कर सकती है, लेकिन लापरवाही बरतने पर झटका भी लग सकता है।

हमारे समुदाय के लिए AI के मायने

हमारे स्थानीय समुदाय के लिए AI विकास की एक नई लहर लेकर आया है

- **शिक्षा-** आज हमारे बच्चे AI टूल्स की मदद से गणित और विज्ञान के जटिल सवाल आसानी से समझ रहे हैं। यह हर बच्चे को एक 'पर्सनल ट्यूटर' देने जैसा है।
- **स्वास्थ्यः** डॉक्टर अब AI की मदद से बीमारियों का पता पहले से अधिक सटीकता से लगा रहे हैं, जिससे इलाज बेहतर हो रहा है।
- **व्यवसायः** हमारे छोटे व्यापारी और दुकानदार AI का उपयोग करके यह समझ सकते हैं कि ग्राहकों को क्या पसंद है और अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए।

सुरक्षा और सावधानी: सिक्के का दूसरा पहलू

हर नई तकनीक के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हाल ही में हमने 'डीपफेक' (Deepfakes) के बारे में सुना है-जहाँ AI का गलत इस्तेमाल करके किसी का भी नकली वीडियो या आवाज बनाई जा सकती है। यह तकनीक जितनी शानदार है, गलत हाथों में उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है।

समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा

- **1. सत्यापन (Verify) करें**- व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर या वीडियो पर आँख मूंदकर भरोसा न करें। AI से बनी नकली खबरें बहुत असली लग सकती हैं। साझा (Share) करने से पहले सोचें - 'क्या यह सच है?'
- **2. अपनी गोपनीयता (Privacy) बचाएं**- मुफ्त AI ऐप्स का इस्तेमाल करते समय ध्यान दें कि आप उन्हें अपनी कौन सी जानकारी दे रहे हैं। आपका डेटा आपकी संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखें।

AI भविष्य है, और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ह्र एक बेहतरीन 'नौकर' है, लेकिन एक खतरनाक 'मालिक' हो सकता है। इसकी लगाम हमेशा इंसान के विवेक और नैतिकता के हाथों में होनी चाहिए।

- **3. तकनीक को सीखें, डरें नहीं**-AI से बचने का नहीं, बल्कि इसे सीखने का समय है। हमें अपने बच्चों और बुजुर्गों को 'डिजिटल साक्षरता' (Digital Literacy) सिखानी होगी ताकि वे ऑनलाइन ठगी का शिकार न बनें।

AI का जिम्मेदार विकासः निष्पक्षता और रोजगार

AI के व्यापक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए, हमें इसके विकास को नैतिक सिद्धांतों पर आधारित करना होगा। भारत अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना AI डेवलपर्स की जिम्मेदारी है कि AI मॉडल किसी एक समुदाय या वर्ग के प्रति पक्षपाती (Biased) न हों। AI सिस्टम को हमारे देश की सभी भाषाओं और बोलियों को समझने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुँच बना सकें।

कौशल और रोजगार का भविष्य

AIनौकरियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है; यह उन्हें बदल रहा है। AI मशीनी और दोहराए जाने वाले (repetitive) कार्यों को स्वचालित (automate) करेगा, जिससे इंसानों के लिए रचनात्मकता (Creativity), समस्या समाधान (Problem-Solving) और मानवीय संपर्क (Human Interaction) वाले क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे।

युवाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है-AIको एक टूल के रूप में देखें, प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं। हमें सरकार और उद्योगों से मिलकर ऐसे कौशल विकास (Skill Development) कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे कार्यबल को AI-संचालित भविष्य के लिए तैयार करें।

AIभविष्य है, और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि AI एक बेहतरीन 'नौकर' है, लेकिन एक खतरनाक 'मालिक' हो सकता है। इसकी लगाम हमेशा इंसान के विवेक और नैतिकता के हाथों में होनी चाहिए।

याद रखें,AIकी सफलता केवल उसकी तकनीकी क्षमता पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे कितनी जिम्मेदारी और न्याय के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं।

आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ तकनीक का उपयोग डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए हो।

जागरूक बनें, सुरक्षित रहें, और AI को जिम्मेदारी से अपनाएं!

बच्चों की नसों में उतरता नशा और हमारी लापरवाही

अनामिका पाण्डेय

अनुज का स्कूल बैग साफ करते वक्त जब उसकी एक किताब के बीच से गुटखे की खाली पन्नी फिसल कर ज़मीन पर गिरी, तो रश्मि का दिल जैसे एक पल को थम सा गया।अनुज अभी सिर्फ़ 11 साल का है। पाँचवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बस्ते में गुटखा? यह सवाल नहीं, एक चेतावनी थी।

रश्मि देर तक उसी पन्नी को देखती रही। दिमाग़ में शोर मच गया। सिर में दर्द होने लगा। अनुज उस समय पार्क में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मन हुआ—अभी बुलाकर पूछे। लेकिन रुक गई। सोचा, पहले उसके पिता को बताएगी। मगर शाम ढल गई, रात बीत गई और वह कुछ नहीं कह पाई। क्योंकि वह जानती थी—अगर बताया तो समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि दोषारोपण शुरू हो जाएगा।

'तुम ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही हो। दिन भर घर में करती क्या हो?,बच्चे पर नज़र क्यों नहीं रखती?, तुमने इसे सिर पर चढ़ा रखा है।' ऐसी बातें, जो ज़हर से कम नहीं होतीं। जिनमें चिंता नहीं, सिर्फ़ आरोप होता है।

अगले दिन अनुज स्कूल से लौटा, बस्ता पटककर खेलने निकल गया। रश्मि ने इस बार पूरा बस्ता उलट-पुलट कर देख डाला। अंदर की जेब से गुटखे की एक पुड़िया निकली—आधी भरी हुई। अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी। शाम को जब अनुज लौटा, तो रश्मि का संयम टूट चुका था। पुड़िया सामने रख कर सवाल किए। अनुज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पहले उसने इनकार किया। लेकिन जब गुस्से में एक थप्पड़ पड़ा, तो रोते हुए सारी कहानी बाहर आ गई।

स्कूल में उसकी दोस्ती आठवीं में पढ़ने वाले दो लड़कों से हो गई थी। वे उसे अपने साथ क्रिकेट खिलाते थे। स्कूल के पीछे मैदान की बाउंड्रीवाल टूटी हुई थी। उसी रास्ते से वे अनुज को बाहर भेजते—सामने की गुमटी से गुटखा लाने। खुद भी खाते, उसे भी चखाते। कभी-कभी अनुज अपनी पॉकेटमनी से भी खरीद लेता।

रश्मि जैसे सुन्न पड़ गई।

कब से?

छह महीने से।

अनुज ने बताया—पहली बार चक्कर आया था, गिर पड़ा था। वही लड़के संभाल कर घर तक छोड़ आए थे।

लेकिन अब,

अब उसे ताक़त महसूस होती है। थकान नहीं लगती। खेल में 'मज़ा' आता है। यही वह क्षण था जब रश्मि को समझ आया—यह सिर्फ़ उसका बच्चा नहीं है। यह एक पूरी पीढ़ी की कहानी है।

यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। देश के दस बड़े शहरों में किए गए एक सर्वे ने बताया है कि बच्चे औसतन 12.9 साल की उम्र में पहली बार किसी नशीले पदार्थ के संपर्क में आ रहे हैं। कुछ तो 11 साल के भी हैं। 'नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट कहती है—हर सात में से एक स्कूल जाने वाला बच्चा कभी न कभी किसी साइकोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, डिब्रूगढ़ और रांची—देश के नामी स्कूलों में यह हाल है। तो ज़रा सोचिए—छोटे शहरों, कस्बों और गलियों में क्या स्थिति होगी? जहाँ स्कूल की दीवार से सटी पान गुमटी खड़ी होती है। नशा यहाँ चोरी-छिपे नहीं बिकता। यह खुलेआम बिकता है। कानून की तख़्तियों के नीचे।

डॉक्टरों ने साफ़ कहा है—जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, नशे की पकड़ गहरी होती जाती है। और इसके साथ बढ़ती है मानसिक परेशानी—व्यवहार की समस्याएँ, अतिसक्रियता, भावनात्मक अस्थिरता। लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई यह है— आधे से ज़्यादा बच्चे मानते हैं कि वे नशा करने की बात छुपाएंगे। यानी जो दिख रहा है, वह पूरा सच नहीं है।

यह सिर्फ़ गुमटियों का अपराध नहीं है। यह सिर्फ़ पुलिस की नाकामी नहीं है। यह हमारे घरों की चुप्पी का नतीजा है। आज के माता-पिता कमाने की दौड़ में इतने उलझे हैं कि बच्चों के मन तक पहुँचने का रास्ता खो चुके हैं। घर में बातचीत की जगह स्क्रीन है। संस्कार की जगह कंटेंट। बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है? किसके साथ खेल रहा है? कौन उसे प्रभावित कर रहा है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं। नशे का कारोबार धीरे-धीरे, बिना शोर के, हमारे बच्चों की नसों में उतर रहा है।यह सामाजिक नरसंहार है—जिसमें लाशें नहीं गिरतीं,लेकिन समाज खोखला हो जाता है। और इस सच्चाई से हम बच नहीं सकते कि इस विनाश की पहली ज़िम्मेदारी, हम माता-पिता की है।

जो समय रहते नहीं देखते।

नहीं सुनते।

और जब तक समझते हैं—

तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

> **दिल्ली की हवा यह नहीं पूछती कि सरकार किस पार्टी की है। वह हर फेफड़े में समान रूप से ज़हर घोलती है। इसलिए यह समय राजनीतिक श्रेय-प्रश्रेय से आगे बढ़ने का है।**

दमघोंटू सियासत में घुटती दिल्ली की हवा

नीरज अग्निहोत्री

दिल्ली में सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं—पर अगर कुछ नहीं बदलता तो वह है राजधानी की हवा। हर चुनाव से पहले वादों की नई परत चढ़ाई जाती है और हर सर्दी में वही परत उतरकर ज़हर बन जाती है। दिल्ली की हवा एक बार फिर सवाल नहीं, बल्कि सजा बन चुकी है। सुबह की शुरुआत अब सूरज की रोशनी से नहीं, धुंध की मोटी चादर से होती है। शाम ढलते-ढलते आंखों में जलन, गले में खराश और सीने की जकड़न जैसे लक्षण आम हो गए हैं। सांस लेना अब सहज क्रिया नहीं, संघर्ष है।

डॉक्टरों की चेतावनी हर साल तेज़ होती जा रही है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और हृदय रोगियों के लिए यह मौसम किसी इमरजेंसी से कम नहीं। बच्चों और बुज़ुर्गों की हालत और ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ़ मौसम की मार है? या फिर यह वर्षों की नीतिगत लापरवाही, राजनीतिक अहंकार और जवाबदेही से बचने की आदत का नतीजा है?

विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल बयानबाज़ी कर रही है। हर साल नवंबर-दिसंबर आते ही 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' जैसे भारी-भरकम नामों की योजनाएं सामने रख दी जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आंकड़े गिनाए जाते हैं—और फिर सब कुछ अगले साल के लिए टाल दिया जाता है। न सड़क की धूल कम होती है, न वाहनों के धुएं पर ठोस नियंत्रण। निर्माण स्थलों पर नियमों की धज्जियां उड़ती रहती हैं और कूड़े के ढेर से उठता धुआं मानो शहर के फेफड़ों को रोज़ जलाता है।

सरकार कहती है कि उसने इलेक्ट्रिक बसें चलाईं, पानी का छिड़काव किया, पराली जलाने पर निगरानी बढ़ाई। सवाल यह नहीं कि योजनाएं घोषित हुईं या नहीं, सवाल यह है कि वे ज़मीन पर कितनी असरदार रहीं? अगर सब कुछ इतना ही प्रभावी था, तो हर साल प्रदूषण का ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? करोड़ों रुपये खर्च हुए—यह सरकारी कागज़ों में दर्ज है। लेकिन अगर जनता को सांस लेने लायक हवा नहीं मिली, तो उस खर्च का औचित्य क्या है?

दिल्ली का प्रदूषण केवल स्थानीय समस्या नहीं है। यह एक क्षेत्रीय संकट है, जिसमें पड़ोसी राज्यों की भूमिका भी जुड़ी है। पराली जलाने से लेकर औद्योगिक धुएं तक, वाहनों की बेतहाशा संख्या से लेकर शहरी अव्यवस्था तक—सब मिलकर इस संकट को गहरा करते हैं। लेकिन यह तर्क देकर सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। राजधानी होने के नाते दिल्ली को उदाहरण बनना चाहिए था, चेतावनी नहीं।

राजनीति यहां सबसे बड़ा प्रदूषक बनकर उभरती है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की धुंध इतनी घनी है कि समाधान की राह दिखाई ही नहीं देती। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार पिछली सरकारों की विफलताओं का हवाला देती है। लेकिन इन बहसों में आम आदमी की सांसें कहीं खो जाती हैं। जनता को यह जानने का हक़ है कि आखिर जवाबदेह कौन है? और कब तक?

दिल्ली की हवा यह नहीं पूछती कि सरकार किस पार्टी की है। वह हर फेफड़े में समान रूप से ज़हर घोलती है। इसलिए यह समय राजनीतिक श्रेय-प्रश्रेय से आगे बढ़ने का है। सरकार को विपक्ष की आलोचना को दुश्मनी नहीं, चेतावनी की तरह लेना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुगम और व्यापक बनाना होगा। निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे—चाहे वे अलोकप्रिय ही क्यों न हों। निर्माण स्थलों, उद्योगों और कूड़ा प्रबंधन पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी।

साथ ही, जनता की भूमिका को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता से अपील तभी असरदार होती है, जब सरकार खुद उदाहरण पेश करे। जब नीति और नियत दोनों साफ हों। आज दिल्ली को किसी और आपातकालीन योजना की नहीं, स्थायी समाधान की ज़रूरत है—ऐसे समाधान की जो सिर्फ़ कागज़ों में नहीं, हवा में महसूस हो।

दिल्ली की हवा आज एक सवाल बन चुकी है—क्या यह शहर सिर्फ़ सत्ता का केंद्र रहेगा या नागरिकों के जीने लायक जगह भी बनेगा? जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हर सर्दी के साथ दिल्ली यूं ही दम तोड़ती रहेगी। और तब इतिहास यह नहीं पूछेगा कि किसने कितना कहा, बल्कि यह पूछेगा कि किसने समय रहते सांसों को बचाने का साहस दिखाया।

झोलाछाप पत्रकार!

नरेन्द्र पाण्डेय

उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए कहा— 'आप झोलाछाप पत्रकार हैं!'

मैंने मुस्कुराकर सिर झुकाया। कोई तकरार नहीं, कोई कटाक्ष नहीं। केवल विनम्रता से कहा—'जी, पत्रकार तो सदैव झोला वाले ही रहे हैं—और गर्व से रहे हैं।'

दरअसल, जनाब, झोला सिर्फ़ कपड़े की थैली नहीं। यह एक विचारधारा है। यह पत्रकारिता की यात्रा है। यह उस ईमानदारी और संवेदना का प्रतीक है, जो किसी प्रेस क्लब की चमकदार चाय में नहीं, बल्कि गाँव की धूल और खेत की मिट्टी में मिलती है।

झोला उस पत्रकार की पहचान है, जो खबरें खरीदता नहीं, तलाशता है। जो किसी आधिकारिक प्रेस नोट की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि सड़क के मोड़ पर बैठे उस आदमी की कहानी सुनता है, जिसकी आवाज़ कभी किसी स्टूडियो की तेज़ रोशनी तक नहीं पहुँचती।

झोला उस ईमान का प्रतीक है, जो लिखने से पहले यह नहीं सोचता— 'किसके हित में?' या 'किसके विरुद्ध?' वह बस यह देखता है कि सच कहाँ दबा है, और किसकी कहानी छुपी हुई है।

> **हम लोग फैंसी लैपटॉप बैग नहीं उठाते। हमारे पास झोला होता है। उस झोले में कोई लग्ज़री नहीं, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ होती है— एक नोटबुक, कुछ पुराने कागज़, एक साधारण कलम, और सबसे ज़रूरी, संवेदना।**

आज 'झोलाछाप' शब्द को अक्सर अपमान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मानो पत्रकारिता की विश्वसनीयता इस बात से तय होती हो कि कैमरा कितना महँगा है, स्टूडियो कितना चमकदार है और एंकर की टाई कितनी ब्रांडेड है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली पत्रकारिता स्टूडियो में नहीं मिलती। झोला लिए चलने वाला पत्रकार सच की खोज में जलता, भीगता और कभी-कभी गाँव की कच्ची सड़क पर पैर गड़ाकर सच्चाई की कसम खाता है। उसके पास न तो भारी-भरकम संसाधन होते हैं, न ही सत्ता के गलियारों में एंट्री कार्ड। उसकी पूँजी सिर्फ़ भरोसा होती है— जनता का भरोसा।

हम लोग फैंसी लैपटॉप बैग नहीं उठाते। हमारे पास झोला होता है। उस झोले में कोई लग्ज़री नहीं, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ होती है— एक नोटबुक, कुछ पुराने कागज़, एक साधारण कलम, और सबसे ज़रूरी, संवेदना। क्योंकि पत्रकारिता स्टूडियो में नहीं मिलती। यह सड़क पर मिलती है। चौपाल में मिलती है।

खेत की मेड़ पर, मजदूर की हथेलियों में, और उस औरत की आँखों में मिलती है, जो कैमरा देखते ही चुप हो जाती है, लेकिन झोला देखकर बोल उठती है।

जो लोग हमें 'झोलाछाप' कहकर अपमान समझते हैं, उन्हें शायद इतिहास याद नहीं। उन्हें यह याद नहीं कि यही झोला कभी गणेश शंकर विद्यार्थी के कंधे पर था, माखनलाल चतुर्वेदी की चाल में झूलता था, और रामवृक्ष बेनीपुरी के शब्दों में सांस लेता था। तब पत्रकारिता मिशन थी, न कि मैनेजमेंट। तब पत्रकार जनता के बीच उतरता था, उनके दर्द को समझता था, उनके सवाल उठाता था।

और यही परंपरा हमें आज भी अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाती है।

तो हाँ, मैं झोलाछाप पत्रकार हूँ—और रहूंगा। क्योंकि मेरा समाचार सत्ता के दरवाज़े से नहीं, जनता की सांसों से निकलता है। क्योंकि मेरे शब्द बिकते नहीं, और मेरा झोला झुकता नहीं। जिस दिन पत्रकारिता से झोला हट गया, उस दिन खबरें फाइलों में बदल जाएँगी।

और पत्रकार— किसी कॉर्पोरेट का एक कर्मचारी बनकर रह जाएगा। जिसे सच नहीं, केवल स्क्रिप्ट पढ़नी होगी।

जनाब, फर्क बस इतना है— झोला अगर गले में हो, तो पत्रकार बनाता है। लेकिन अगर झोला पेट में हो, तो दलाल बना देता है। और उस दिन, उनके तिरस्कार पर मेरा मुस्कुराना हावी हो गया। कमरे में सन्नाटा था— क्योंकि झोला बोल चुका था।

पुराने भवन में आखिरी बार गूंजा सदन

छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 23 वर्षों की संसदीय यात्रा को किया याद

छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र हुआ, जो पुराने विधानसभा भवन का आखिरी सत्र रहा। इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के नेताओं अपने संसदीय अनुभव साझा किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संसदीय यात्रा को याद करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की यात्रा में 23 साल इसका गवाह रहा हूं। 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में, पांच साल विपक्ष में और अभी विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से एक अनुभव छत्तीसगढ़ की विधानसभा से जुड़ी है। विकास की सारी गाथाएं, सारे काम आज मील का पत्थर है। न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एक्ट इसी विधानसभा का चमत्कार है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा, एक रुपया किलो चावल भी दिया, गुड़, चना भी दिया. सब इसी विधानसभा का चमत्कार है. बच्चों के लिए उनके कौशल के लिए इन्स्टीट्यूट खड़ा करना, कौशल विकास के लिए सभी जिलों में इकाई स्थापित करना इसी विधानसभा से हुआ। 16% से ब्याज दर को घटाकर शून्यत्न ब्याज दर में सरकारी बैंक से कर्ज देने का काम इसी विधानसभा से हुआ। एक मेडिकल कॉलेज से अब 15 मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज से 84 नर्सिंग कॉलेज, 212 कॉलेज से 400 ज्यादा का कॉलेज, 40,000 शाला भवन सभी स्तरों के स्कूलों का निर्माण, पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क का नेटवर्क, 15-20000 किलोमीटर तक कार नेशनल हाईवे का काम, 30 हज़ार किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम का प्रस्ताव इसी विधानसभा से पास हुआ।

उन्होंने कहा, 15 और और पांच साल करके बीस साल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काम करने को मिला। यह विधानसभा कभी जल संसाधन विभाग का रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहला विधानसभा टेंट में लगाया गया। उसके बाद विधानसभा यहां शिफ्ट हुआ। अब नया विधानसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुभारंभ हुआ है। ये यादें है विकास की यात्रा के संस्मरण है, विकास की गाथा है।

रमन सिंह ने कहा, इस मिट्टी से इस भूमि से जुड़ा हुआ था। यहां से जाने से पहले उस आसंदी का पैर छूकर जाऊंगा, क्योंकि यही वो आसंदी है, जो मुझे नए दायित्व की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत किया और मैं समझता हूँ कि विधानसभा का अध्यक्ष बनना, मुख्यमंत्री का दायित्व 15 साल का, एक संवैधानिक दायित्व पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर विधानसभा की मान मर्यादा सम्मान को बढ़ाकर बजट प्रस्तुत करने से लेकर नया क़ानून बनाने तक अवसर दिया इसलिए इसे मैं अपने लिए गौरवशाली मानता हूं। आज विधानसभा में 25 वर्ष में पच्चीस सदस्यों ने भाषण में भाग लिया, जिसमें 15 BJP और 10 कांग्रेस से हैं। 25 व रजत जयंती वर्ष और 25 लोगों के भाषण बहुत अच्छे वातावरण में आज रजत जयंती वर्ष पूरा हुआ। अब नए विधानसभा में नए परिवेश में नए वातावरण के साथ आपके साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, मीडिया के साथियों ने छत्तीसगढ़ की बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की मीडिया काम करता है। इसका उदाहरण मैं देश के दूसरे कोने में देता हूं कि मीडिया देखना है तो छत्तीसगढ़ जरूरत आएं।

'नमन तुझे मेरी विधानसभा......

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर आसंदी को प्रणाम करते तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि 'नमन तुझे मेरी विधानसभा, तू लोकतंत्र का आधार रही। जब यहाँ विचारधाराएँ जुटी, तू वटवृक्ष की भांति छांव बनी। यह भवन मेरा विद्यालय था, जिससे आगे अब जाना है। मैं भावुक हूं, आशान्वित हूं, तेरे महत्व को ऐसे पहचाना है। है प्रण मेरा कि सब अर्पित करके भी नए सदन को नव गरिमा तक पहुंचाना है।नमन तुझे मेरी विधानसभा.'

मन का युद्ध भूमि

NLP

।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ।।

और जब व्यक्ति डरता है, तो वह असुरक्षा का दोष किसी और पर डालना चाहता है। यह मन की वह युक्ति है जहाँ व्यक्ति Control में नहीं होता, तो वह भाषा और रिश्तों में नियंत्रण खोजता है। दुर्योधन यहाँ सीधे किसी एक योद्धा की तारीफ़ नहीं कर रहा। वह तुलना कर रहा है

नरेन्द्र पाण्डेय

गतांक से आगे

श्लोक 4-6-दुर्योधन के डर का नक्शा

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः॥
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः॥
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥

दुर्योधन पांडव सेना के योद्धाओं को गिनाता है - भीम और अर्जुन जैसे शूरवीर, युयुधान (सात्यकि), विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पाँच पुत्र - सभी महारथी।

दुर्योधन यहाँ पांडवों की ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहा है। पांडव सेना के योद्धाओं को गिन रहा है, जैसे कोई अपने डर का नक्शा बना रहा हो। हर नाम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती है। 'भीमार्जुनसमा' कहकर वह उनकी शक्ति को बड़ा करता है, ताकि अपनी सेना को सतर्क और खुद को पीड़ित दिखा सके। दुर्योधन यहाँ सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं कर रहा, बल्कि वह धृतराष्ट्र के अवचेतन को पाण्डवों की सामर्थ्य की भयावहता से परिचित कर रहा है। यह वह समय है जब मनुष्य अपनेशत्रु की सामर्थ्यगिनता है – लेकिन उस गिनती मेंडर की झलक, अदृश्य चिंता, औरअंतर्मन की उलझनें छिपी होती हैं। हर नाम के साथ 'महारथी', 'वीर्यवान', 'नरपुंगव' जैसे विशेषणों का प्रयोग करता है। यह न केवल पाण्डवों की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह धृतराष्ट्र के मानसिक भय को और अधिक उभारता है। यह NLP में "Language Framing" कहलाता है – यानी भाषा के द्वारादृष्टिकोण को मोड़ना।जब एक मन भयभीत होता है, तब वह अपनेशत्रु की शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकरदेखने लगता है। और जब एक मन सजग होता है, तब वहशत्रु की शक्ति को गहराई से समझताहै।

'भीम-अर्जुन के समान' कहकर वह Comparison कर रहा है और पांडवों की ताकत को बड़ा दिखाता शत्रु को विशाल बताकर अपने पक्ष को कमजोर दिखाना।

- युयुधान (कृष्ण का शिष्य), विराट (पांडवों का सहयोगी), द्रुपद (द्रोण का शत्रु) - ये नाम द्रोण के मन में भावनात्मक (Emotional) उलझन पैदा करते हैं।
- वह बार-बार दुश्मन की ताकत गिन रहा है, जैसे उसका मन एक भय (threat) चक्र में फँस गया हो।

दुर्योधन डर से नहीं, बल्कि गुरु की निष्ठा को परखने के लिए यह सब कह रहा है। वह अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है - 'आचार्य, अब आप किसके साथ हैं?' आज का संदर्भमे देखे तो , जब हम किसी से डरते हैं, तो उनकी ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर देखते हैं- 'उसके पास ये है, वो है' यह डर का वह चक्र है जो हमें कमजोर बनाता है।

डर किस बात का , यहाँ दुर्योधन 'पांडवों की सेना' को देखकर घबरा रहा है, जबकि उसके पास संख्या में बड़ी सेना, शक्तिशाली योद्धा, और गुरु स्वयं मौजूद हैं।

तो डर किस बात का? दरअसल डर तब होता है जब हमारी Inner Identity कमजोर हो। यानी – बाहर से ताक़तवर दिखने वाले लोग भी अंदर सेथर-थर काँपते हैं, अगर उनका "why" स्पष्ट नहीं है।

क्योंकि दुर्योधन डर रहा है –

और जब व्यक्ति डरता है, तो वह असुरक्षा का दोष किसी और पर डालना चाहता है। यह मन की वह युक्ति है जहाँ व्यक्ति Control में नहीं होता, तो वह भाषा और रिश्तों में नियंत्रण खोजता है। दुर्योधन यहाँ सीधे किसी एक योद्धा की तारीफ़ नहीं कर रहा। वह तुलना कर रहा है – ताकि value perception बने- 'देखो! सामने वाले कैंप में सिर्फ़ अर्जुन-भीम नहीं हैं, उनके जैसे कई हैं।'

'युयुधान, विराट, द्रुपद' ये नाम यूँ ही नहीं आए। इनमें से युयुधान (सात्यकि) श्रीकृष्ण का शिष्य है, विराट – वह राजा है जिसके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, द्रुपद – द्रोणाचार्य का शत्रु और धृष्टद्युम्न का पिता। दुर्योधन ये नाम ले रहा है ताकि गुरु द्रोण के भीतर Emotional Conflict पैदा हो – 'देखो, तुम्हारा शत्रु भी उनके साथ खड़ा है।' पर ये डर से नहीं, बल्कि गुरु की Loyalty Test करने के लिए है।

जैसे कोई कहे – 'अब तो आप ही बताएँ आचार्य – ऐसे हालात में आप किस ओर खड़े हैं?'

अब गौर कीजिए – दुर्योधन यहाँ अभिमन्यु का ज़िक्र करता है, जो अभी युवा है, पर उसे महारथी कहता है। यह ज़ाहिर करता है कि-

- या तो वह पांडव पक्ष की शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहा है,
- या फिर वहगुरु द्रोण को इमोशनली प्रभावितकरना चाहता है,

क्योंकि अभिमन्यु – अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र – कृष्ण का भांजा है।

यहां वो indirectly श्रीकृष्ण की मौजूदगी का shadow reference दे रहा है। द्रौपदी की संतानों का नाम लेकर दुर्योधन उस अपमानकी गूँज भी subtly जगा देता है, जो उसने कभी द्रौपदी के साथ किया था। आज की दुनिया में उदाहरण- मान लीजिए दो टीमें किसी Project पर टकरा रही हों, और एक Team Leader कहे- 'उनकी टीम में तो सीनियर डेवेलपर हैं, पिछले साल के अवॉर्ड विनर हैं, और वो भी है जो तुम्हारा ही स्टूडेंट रहा है।'

इसमें एक subtle message छिपा होता है –'उनकी काबिलियत देखकर घबराओ नहीं, लेकिन सोचो कि वो लोग अब तुम्हारे खिलाफ़ हैं।' यहाँ एक बात समझिए कि इन सबका ज़िक्र वह पांडवों की सेना के संदर्भ में कर रहा है, न कि अपनी तरफ़ से। यानी अभी भी वह अपनी सेना की बात नहीं कर रहा – वह सिर्फ़ पांडव पक्ष की ताक़त को उभार रहा है।

अक्सर जब कोई व्यक्ति भीतर से असुरक्षित हो, पर बाहर से साहसी बनने का अभिनय कर रहा हो। तो दूसरे की शक्ति को बड़ा करके दिखाते हैं, ताकि अपनी स्थिति को संकट में दिखा सकें।

जब भी हम डरते हैं, तो हमारा दिमाग़ हर संभावित 'शत्रु' की लिस्ट बनाता है। दुर्योधन भी इन योद्धाओं के नाम इसलिए गिना रहा है क्योंकि वह मानसिक तौर पर ख़तरे का नक्शा बना रहा है।

गहराई से देखें तो...

दुर्योधन की हर बात में एक emotional manipulation है। वह सीधे युद्ध नहीं कर रहा,बल्कि पहले अपने लोगों के दिमाग़ में युद्ध का माहौल बना रहा है। यही तो युद्ध की असली शुरुआत होती है। लेकिन जब मन एक ही प्रकार की सोच में अटक जाता है, खासकर डर, तनाव या असहायता की स्थिति में। यह एक Anxiety के लक्षण है दुर्योधन भले शांत दिखता हो, पर भीतर उसका मन Anxiety में फँसा है।

दुर्योधन जिस क्रम से नाम गिनाता है – वह आंतरिक तनाव की Progressive Unfolding है। पहले बड़े योद्धा, फिर विशेष पात्र, फिर भावनात्मक रूप से जुड़े लोग। यह वह तरीका है जिससे इंसान अपने डर को layer by layer खोलता है।

क्रमशः.....

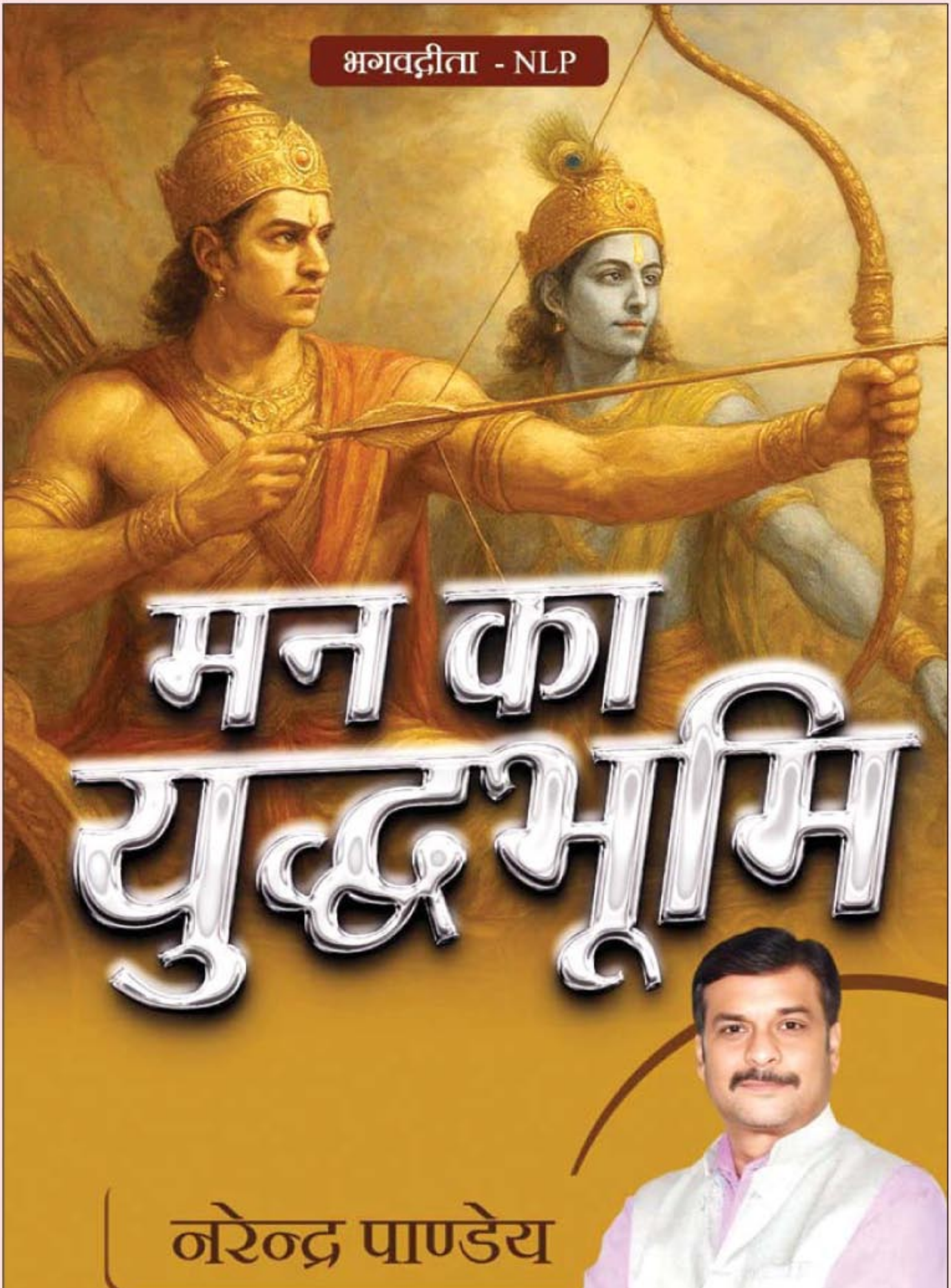
भगवद्गीता - NLP
मन का
युद्धभूमि
नरेन्द्र पाण्डेय

www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic Health Care System

Unique Wellbeing Center

Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing

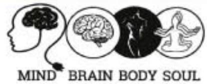

1. **Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-**

   Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.

2. **Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -**

   Personality Analysis Body Type, Mind Type, Energy Type.

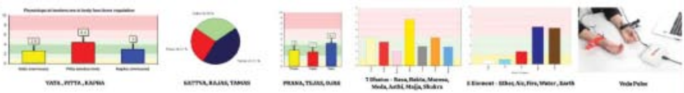

3. **Life Style Clinic**

   Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.

4. **Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.**

5. **Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.**

6. **Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.**

Get In Touch
9109185028, 9109185025

A-41, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com